कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत कृषि अखबार

Registered Postal Regn. No.MP/Bhopal/143/2025-27 RNI No. 1832/57 डाक प्रेषण का दिन - सोमवार, मंगलवार

कृषक जगत

राष्ट्रीय कृषि अखबार

भोपाल-जयपुर-रायपुर ISSN -0970-8650

संस्थापित 1946 भोपाल, प्रकाशन - सोमवार, 2 मार्च 2026 वर्ष - 80 अंक - 27 मूल्य - रु. 12/- कुल पृष्ठ -16 www.krishakjagat.org पृष्ठ- 1

कृषक जगत न्यूज़ वेबसाइट पर जाने के लिए QR कोड स्कैन करें

श्रेष्ठ कृषि पत्रकारिता के लिए भाकृअनुप ICAR चौधरी चरणसिंह अवार्ड से पुरस्कृत

अंदर पढ़िये...

होली की हार्दिक शुभकामनाएं

कृषक जगत के सुधी पाठकों, विज्ञापनदाताओं, प्रतिनिधियों एवं शुभ चिंतकों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।

- कृषक जगत परिवार

पूसा कृषि विज्ञान मेला 2026

किसानों के बकाया भुगतान पर 12% ब्याज

श्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि सुधारों का रोडमैप रखा

नई दिल्ली (कृषक जगत)। केंद्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) में पूसा कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन करते हुए लाइसेंस प्रक्रिया, सब्सिडी वितरण आदि से जुड़े कृषि सुधारों का रोडमैप प्रस्तुत किया।

आईसीएआर-आईएआरआई परिसर में आयोजित इस वार्षिक मेले में वैज्ञानिकों, प्रगतिशील किसानों, कृषि उद्यमियों और नीति-निर्माताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ पौधारोपण से हुआ। इस मौके पर कृषि सचिव श्री देवेश चतुर्वेदी, आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. एम. एल. जाट और आईएआरआई के निदेशक डॉ. सी. एच. श्रीनिवास राव सहित कई अधिकारी और किसान उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सात किसानों को आईएआरआई कृषि अध्येता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। **(शेष पृष्ठ 2 पर)**

डॉ. मोहन यादव का 'कृषक कल्याण वर्ष 2026'

घोषणाओं से आगे, क्रियान्वयन की कसौटी पर कसता एजेंडा

भोपाल (कृषक जगत)। म.प्र. विधानसभा के सत्र के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वर्ष 2026 को 'कृषक कल्याण वर्ष' के रूप में मनाने की घोषणा करते हुए किसानों के सशक्तिकरण को प्रदेश के सर्वांगीण विकास की आधारशिला बताया। उनका यह वक्तव्य केवल औपचारिक घोषणा नहीं, बल्कि कृषि राजनीति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के केंद्र में किसान को पुनः स्थापित करने का प्रयास है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार किसान को केवल 'अन्नदाता' नहीं, बल्कि 'ऊर्जादाता' और 'उद्यमी' के रूप में भी देखना चाहती है। यह दृष्टिकोण पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर वैल्यू एडिशन, फसल विविधीकरण और कृषि-आधारित उद्यमिता की दिशा में संकेत देता है। हालांकि, असली सवाल यही है कि क्या घोषित योजनाएँ जमीनी स्तर पर समयबद्ध और पारदर्शी क्रियान्वयन तक पहुँच पाएंगी?

सरसों: भावांतर योजना का दायरा बढ़ा, लेकिन भुगतान की गति अहम

सरसों के रकबे में 28 प्रतिशत वृद्धि और 15.71 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित उत्पादन के बीच सरकार ने भावांतर योजना के तहत सरसों को शामिल करने का निर्णय लिया है। जनवरी में औसत मंडी दर 6000 रुपये प्रति क्विंटल रही, जबकि केंद्र द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 6200 रुपये है। सरकार का प्रस्ताव है कि एफएक्यू सरसों पर एमएसपी से कम मूल्य मिलने पर अंतर की प्रतिपूर्ति की जाए। पंजीकृत किसानों को रकबे और औसत उत्पादकता के आधार पर भुगतान किया जाएगा।

यह कदम सराहनीय है, परंतु पिछली योजनाओं का अनुभव बताता है कि भुगतान में देरी और पात्रता निर्धारण की जटिल प्रक्रिया किसानों के उत्साह को कम करती है। यदि भुगतान त्वरित और पारदर्शी हुआ, तभी यह निर्णय सरसों उत्पादकों के लिए वास्तविक राहत साबित होगा।

उड़द पर रु. 600 बोनस: फसल विविधीकरण की रणनीति

ग्रीष्मकालीन मूंग के अधिक उत्पादन से उत्पन्न विपणन संकट को देखते हुए सरकार ने उड़द पर 600 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। यह बोनस एमएसपी के अतिरिक्त होगा और मूंग की जगह उड़द बोने के लिए प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा। **(शेष पृष्ठ 3 पर)**

ऑनलाईन सदस्यता के लिए लॉग इन करें
www.krishakjagat.org

ग्रीष्मकालीन बुवाई 2026 की शुरुआत सकारात्मक

20 फरवरी तक 21.30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई

(निमिष गंगराड़े)

नई दिल्ली (कृषक जगत)। देश में ग्रीष्मकालीन फसलों की बुवाई ने रफ्तार पकड़ ली है। 20 फरवरी 2026 तक कुल 21.30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई हो चुकी है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह आंकड़ा 20.38 लाख हेक्टेयर था। इस प्रकार चालू वर्ष में 0.92 लाख हेक्टेयर की वृद्धि दर्ज की गई है। यह आंकड़े कृषि मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं।

वर्ष 2022-23 से 2024-25 के औसत के आधार पर ग्रीष्मकालीन फसलों का सामान्य क्षेत्र 75.37 लाख हेक्टेयर है। वर्ष 2025 में ग्रीष्मकालीन फसलों का अंतिम क्षेत्र 83.92 लाख हेक्टेयर रहा था, जो सामान्य क्षेत्र से अधिक था।

धान की बुवाई स्थिर

धान की बुवाई 17.78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हुई है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के बराबर है। धान का सामान्य ग्रीष्मकालीन क्षेत्र 31.49 लाख हेक्टेयर है, जबकि वर्ष 2025 में अंतिम क्षेत्र 33.28 लाख हेक्टेयर रहा था। शुरुआती चरण में धान की बुवाई का स्थिर रहना संकेत देता है कि प्रमुख सिंचित क्षेत्रों में बुवाई सामान्य गति से चल रही है।

दलहनों में बढ़ोतरी

दलहनों का कुल क्षेत्र 0.91 लाख हेक्टेयर रहा है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 0.76 लाख हेक्टेयर से 0.15 लाख हेक्टेयर अधिक है। मूंग की बुवाई 0.59 लाख हेक्टेयर में हुई है, जो

पिछले वर्ष के 0.56 लाख हेक्टेयर से अधिक है। उड़द का क्षेत्र 0.25 लाख हेक्टेयर है, जबकि पिछले वर्ष यह 0.19 लाख हेक्टेयर था। अन्य दलहनों का क्षेत्र 0.07 लाख हेक्टेयर दर्ज किया गया है, जो पिछले वर्ष 0.01 लाख हेक्टेयर था।

दलहनों का सामान्य ग्रीष्मकालीन क्षेत्र 23.40 लाख हेक्टेयर है और वर्ष 2025 में अंतिम क्षेत्र 27.07 लाख हेक्टेयर रहा था।

श्री अन्न एवं मोटे अनाज में विस्तार

श्री अन्न एवं मोटे अनाज का कुल क्षेत्र 1.38 लाख हेक्टेयर पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 1.08 लाख हेक्टेयर से 0.30 लाख हेक्टेयर अधिक है। ज्वार का क्षेत्र 0.04 लाख हेक्टेयर है, जबकि पिछले वर्ष यह 0.03 लाख हेक्टेयर था। बाजरा 0.12 लाख हेक्टेयर में बोया गया है, जो पिछले वर्ष के 0.14 लाख हेक्टेयर से थोड़ा कम है। रागी का क्षेत्र 0.15 लाख हेक्टेयर पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष 0.02 लाख हेक्टेयर था। छोटे मिलेट्स का क्षेत्र 0.01 लाख हेक्टेयर है। मक्का 1.06 लाख हेक्टेयर में बोया गया है, जो पिछले वर्ष के 0.89 लाख हेक्टेयर से अधिक है।

इस श्रेणी का सामान्य क्षेत्र 12.08 लाख हेक्टेयर है, जबकि वर्ष 2025 में अंतिम क्षेत्र 14.06 लाख हेक्टेयर रहा था।

तिलहनों में तेज वृद्धि

तिलहनों का कुल क्षेत्र 1.24 लाख हेक्टेयर हो गया है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 0.77 लाख हेक्टेयर से 0.46 लाख हेक्टेयर अधिक है। मूंगफली 1.04 लाख हेक्टेयर में बोई गई है, जो पिछले वर्ष के 0.60 लाख हेक्टेयर से काफी अधिक है। सूरजमुखी 0.07 लाख हेक्टेयर में बोया गया है, जो पिछले वर्ष 0.06 लाख हेक्टेयर था। तिल का क्षेत्र 0.12 लाख हेक्टेयर है, जो पिछले वर्ष के बराबर है। अन्य तिलहनों का क्षेत्र 0.01 लाख हेक्टेयर दर्ज किया गया है।

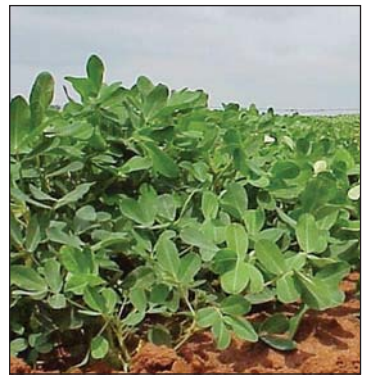

तिलहनों का सामान्य ग्रीष्मकालीन क्षेत्र 8.40 लाख हेक्टेयर है, जबकि वर्ष 2025 में अंतिम क्षेत्र 9.51 लाख हेक्टेयर रहा था।

कुल स्थिति

कुल मिलाकर 20 फरवरी 2026 तक 21.30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन फसलों की बुवाई हो चुकी है। दलहन, मोटे अनाज और तिलहन में वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि धान का क्षेत्र स्थिर है। आगामी सप्ताहों में सिंचाई की उपलब्धता और मौसम की स्थिति के आधार पर बुवाई का रकबा और बढ़ने की संभावना है।

ग्रीष्मकालीन फसलों के अंतर्गत क्षेत्र प्रगति (क्षेत्रफल : लाख हेक्टेयर में)

क्र.	फसल	सामान्य ग्रीष्म क्षेत्र (DES)*	अंतिम ग्रीष्म क्षेत्र 2025	चालू वर्ष 2026	पिछले वर्ष की समान अवधि 2025	वृद्धि/ कमी
1.	**धान**	**31.49**	**33.28**	**17.78**	**17.78**	**0.00**
2.	**दलहन**	**23.40**	**27.07**	**0.91**	**0.76**	**0.15**
a	मूंग	20.44	23.49	0.59	0.56	0.03
b	उड़द	2.96	3.58	0.25	0.19	0.06
c	अन्य दलहन	0.00	–	0.07	0.01	0.00
3.	**मोटे अनाज**	**12.08**	**14.06**	**1.38**	**1.08**	**0.30**
a	ज्वार	0.34	0.36	0.04	0.03	0.02
b	बाजरा	4.43	5.20	0.12	0.14	-0.03
c	रागी	0.31	–	0.15	0.02	0.13
d	छोटे मिलेट्स	0.02	–	0.01	0.00	0.01
e	मक्का	6.98	8.50	1.06	0.89	0.17
4.	**तिलहन**	**8.40**	**9.51**	**1.24**	**0.77**	**0.46**
a	मूंगफली	3.40	4.20	1.04	0.60	0.44
b	सूरजमुखी	0.34	0.35	0.07	0.06	0.01
c	तिल	4.66	4.96	0.12	0.12	0.00
d	अन्य तिलहन	0.00	–	0.01	0.00	0.01
	कुल	**75.37**	**83.92**	**21.30**	**20.38**	**0.92**

*सामान्य क्षेत्र वर्ष 2022-23 से 2024-25 के औसत पर आधारित है।

पूसा मेले में आईपीएल की सक्रिय भागीदारी

नई दिल्ली (कृषक जगत)। नई दिल्ली, पूसा कृषि विज्ञान मेले में देशभर की उर्वरक, कीटनाशक और कृषि क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों ने भाग लिया और किसानों को उर्वरक प्रबंधन, फसल पोषण तथा आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी।

इंडियन पोटाश लिमिटेड (आईपीएल) ने अपने तीन स्टॉल को एकीकृत कर एक समग्र कृषि स्टॉल स्थापित किया, जो आकर्षण का केंद्र रहा। यहां संतुलित उर्वरक प्रबंधन, फसल पोषण, पशु आहार, डेयरी एवं शुगर सेक्टर से जुड़े उत्पादों की जानकारी प्रदान की गई। किसानों को साहित्य वितरित किए गए। आईपीएल ने किसानों को 6R सिद्धांत-सही स्रोत, सही मात्रा, सही विधि, सही समय, उर्वरकों का सही संयोजन और जल का सही प्रबंधन-अपनाने के लिए प्रेरित किया। कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि मेले के दौरान कृषि विशेषज्ञों ने किसानों से सीधा संवाद किया और आधुनिक पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेज (POPs) पर मार्गदर्शन प्रदान किया।

क्रॉपलाइफ ने सुरक्षित फसल संरक्षण पर दिया जोर

नई दिल्ली। क्रॉपलाइफ इंडिया ने पूसा कृषि विज्ञान मेला 2026 में फसल संरक्षण उत्पादों के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाया। क्रॉपलाइफ इंडिया ने अपने स्टॉल पर किसानों को सही खुराक, सुरक्षित छिड़काव, भंडारण नियम और उत्पाद की प्रामाणिकता की जांच संबंधी जानकारी दी। किसानों को सलाह दी गई कि वे केवल

लाइसेंसधारी विक्रेताओं से ही उत्पाद खरीदें, पक्का बिल लें, पैकेजिंग व एक्सपायरी तिथि जांचें और लेबल निर्देशों का पालन करें, ताकि नकली व अवैध उत्पादों से बचा जा सके। स्टॉल का मुख्य आकर्षण लोक शैली में प्रस्तुत जागरूकता गीत रहा-

'गांव गांव टोले टोले घर घर अलख जगाना है,
कीटनाशक उपयोग को जिम्मेदारी से निभाना है।'

इस प्रस्तुति के माध्यम से छिड़काव की मात्रा, मिश्रण विधि, प्रतीक्षा अवधि और सुरक्षा सावधानियों जैसे तकनीकी संदेशों को सरल भाषा में समझाया गया।

पूसा कृषि विज्ञान मेला... (प्रथम पृष्ठ का शेष)

समयबद्ध भुगतान और वित्तीय जवाबदेही: श्री चौहान ने कहा कि यदि कोई एजेंसी या राज्य सरकार किसानों का भुगतान रोकती है, तो उसे बकाया राशि पर 12 प्रतिशत ब्याज देना होगा। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) का उल्लेख करते हुए कहा कि लगभग 75 प्रतिशत छोटे किसान प्रभावी 4 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण प्राप्त कर रहे हैं। ऋण वितरण में देरी मंजूर नहीं है और बैंकों को समयबद्ध तथा सरल प्रक्रिया सुनिश्चित करनी होगी।

योजनाओं की निगरानी, केवीके की भूमिका और लाइसेंस सुधार : कृषि यंत्रीकरण, ड्रिप, स्प्रिंकलर, पालीहाउस और ग्रीनहाउस जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार 18 से अधिक योजनाओं के तहत राज्यों को संसाधन उपलब्ध कराती है। हालांकि, केवल धन जारी करना पर्याप्त नहीं है; यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि लाभ वास्तविक किसानों तक पहुँचे। एक जिले का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि सूची में 700 किसानों के नाम होने के बावजूद केवल 158 किसानों को मशीनें मिलीं। निगरानी तंत्र को मजबूत किया जाएगा।

एमएसपी, सब्सिडी और 'विकसित कृषि संकल्प अभियान' : न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की वर्तमान तीन महीने की समय-सीमा को अव्यावहारिक बताते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के पास लंबे समय तक भंडारण की क्षमता नहीं होती। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्यों के साथ मिलकर अधिकतम एक महीने में खरीद प्रक्रिया पूरी करने की व्यवस्था बनाई जाए, ताकि किसानों को शीघ्र भुगतान मिल सके। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार खाद सब्सिडी पर लगभग 2 लाख करोड़ रुपये खर्च करती है। इस पर विचार किया जाना चाहिए कि सब्सिडी सीधे किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से दी जाए, ताकि किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार उर्वरक का चयन कर सकें। श्री चौहान ने 'विकसित कृषि संकल्प अभियान' का उल्लेख करते हुए कहा कि अप्रैल से खरीफ सीजन से पहले वैज्ञानिकों की टीमें गांव-गांव जाकर किसानों से सीधा संवाद करेंगी।

कृषि में चमका मध्यप्रदेश

खाद्यान्न, दलहन और तिलहन उत्पादन में देश के शीर्ष तीन राज्यों में मजबूती से स्थापित : डॉ. यादव

खाद्यान्न, दलहन और तिलहन उत्पादन में अग्रणी स्थान

भोपाल (कृषक जगत)। मध्य प्रदेश ने कृषि उत्पादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सशक्त पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य खाद्यान्न, दलहन और तिलहन उत्पादन में देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है। 46.63 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन के साथ प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है, जबकि दलहन में प्रथम और तिलहन में द्वितीय स्थान प्राप्त कर कृषि क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। राज्य सरकार ने वर्ष 2026 को 'किसान कल्याण वर्ष' के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, जिससे किसानों की आय और समग्र विकास को और गति मिलेगी।

खाद्यान्न उत्पादन में देश में दूसरा स्थान

मध्य प्रदेश ने खाद्यान्न उत्पादन में देश में दूसरा स्थान हासिल किया है।

गेहूं : 24.51 मिलियन टन उत्पादन, लगभग 20.78% राष्ट्रीय हिस्सेदारी।

मक्का : 6.64 मिलियन टन उत्पादन, करीब 15.30% हिस्सेदारी- राज्य प्रमुख उत्पादकों में शामिल।

मोटा अनाज (न्यूट्री/कोर्स सीरियल्स): 7.78 मिलियन टन उत्पादन, लगभग 12.17% हिस्सेदारी के साथ देश में तीसरा स्थान।

दलहन में नंबर वन

राज्य ने दलहन उत्पादन में देश में पहला स्थान बनाए रखा है।

कुल दलहन उत्पादन: 5.24 मिलियन टन (20.40% राष्ट्रीय हिस्सेदारी)।

चना : 2.11 मिलियन टन उत्पादन, लगभग 19.01% हिस्सेदारी के साथ देश में दूसरा स्थान।

तिलहन में मजबूत स्थिति

तिलहन उत्पादन में भी मध्यप्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में है।

कुल तिलहन उत्पादन : 8.25 मिलियन टन (लगभग 19.19% हिस्सेदारी)- देश में दूसरा स्थान।

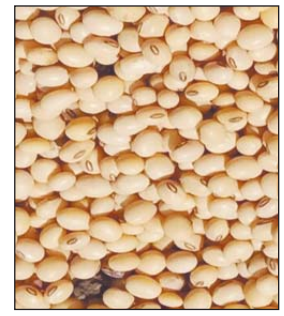

सोयाबीन : 5.38 मिलियन टन उत्पादन, जो देश के कुल उत्पादन का लगभग 35.27% है - राज्य प्रमुख सोयाबीन उत्पादक।

मूंगफली : 1.55 मिलियन टन उत्पादन, 12.99% हिस्सेदारी के साथ देश में तीसरा स्थान।

योजनाओं का असर

मुख्यमंत्री ने बताया केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से यह सफलता मिली है। इनमें उर्वरक वितरण, पौध संरक्षण कार्यक्रम, फसल विविधीकरण, 'एक जिला-एक उत्पाद' योजना, राज्य मिलेट मिशन, किसान उत्पादक संगठन (FPO), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और भावांतर भुगतान जैसी योजनाएं शामिल हैं।

गेहूँ खरीदी के लिये 4 लाख 42 हजार से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया

भोपाल। रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिये अब तक 4 लाख 42 हजार 288 किसानों ने पंजीयन करा लिया है। किसान 7 मार्च तक पंजीयन करा सकते हैं।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों से अपील की है कि निर्धारित समय में पंजीयन जरूर करा लें। उन्होंने बताया है कि किसान पंजीयन की व्यवस्था को सहज और सुगम बनाया गया है। कुल 3186 पंजीयन केन्द्र बनाये गए हैं। केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 के लिये गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2585 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है, जो गत वर्ष से 160 रुपये अधिक है। श्री राजपूत ने बताया कि अभी तक इंदौर संभाग में 54 हजार 587, उज्जैन में एक लाख 48 हजार 905, ग्वालियर में 9695, चम्बल में 4692, जबलपुर में 39 हजार 885, नर्मदापुरम में 34 हजार 181, भोपाल में एक लाख 9 हजार 134, रीवा में 13 हजार 260, शहडोल में 2551 और सागर में 25 हजार 398 किसानों ने पंजीयन कराया है।

डॉ. मोहन यादव का 'कृषक कल्याण वर्ष 2026' (प्रथम पृष्ठ का शेष)

यह निर्णय फसल संतुलन और बाजार प्रबंधन की दृष्टि से व्यावहारिक प्रतीत होता है। परंतु, किसानों को यह भरोसा भी चाहिए कि उड़द की खरीद सुचारु होगी और भुगतान समय पर मिलेगा। केवल बोनस घोषणा से नहीं, बल्कि सुनिश्चित उपार्जन व्यवस्था से ही यह नीति सफल होगी।

चना-मसूर: समर्थन मूल्य पर उपार्जन का प्रस्ताव

चना (6.49 लाख मीट्रिक टन) और मसूर (6.01 लाख मीट्रिक टन) के लिए प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। 24 मार्च से 30 मई 2026 तक उपार्जन अवधि प्रस्तावित है, जबकि 20 फरवरी से 16 मार्च तक पंजीयन की प्रक्रिया जारी है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण पहलू है- खरीदी केंद्रों की पर्याप्त संख्या, भंडारण क्षमता और समय पर भुगतान। यदि प्रशासनिक तैयारी मजबूत रही, तो दलहन उत्पादकों को बड़ा संबल मिलेगा; अन्यथा भीड़, विलंब और गुणवत्ता विवाद जैसी समस्याएँ दोहराई जा सकती हैं।

तुअर : केंद्रीय एजेंसियों से सीधा उपार्जन

तुअर के लिए 1.31 लाख मीट्रिक टन उपार्जन का प्रस्ताव केंद्र को भेजा जा रहा है, जिसे नाफेड और एनसीसीएफ जैसी केंद्रीय एजेंसियाँ सीधे खरीदेंगी। यह मॉडल राज्य के वित्तीय बोझ को कम कर सकता है, परंतु समन्वय की कमी होने पर किसानों को भुगतान और तौल संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

घोषणाओं से आगे-कृषि नीति की व्यापक दिशा

मुख्यमंत्री ने सिंचाई के लिए बिजली-पानी की उपलब्धता, कृषि ऋण और फसल विविधीकरण पर भी जोर दिया। यदि इन घोषणाओं को एक समग्र कृषि रोडमैप के रूप में देखा जाए, तो यह स्पष्ट है कि सरकार उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ बाजार-संतुलन और आय वृद्धि पर ध्यान दे रही है।

फिर भी, कुछ बुनियादी प्रश्न बने हुए हैं:

● क्या राज्य के पास पर्याप्त बजटीय प्रावधान है? ● क्या भुगतान सीधे और समयबद्ध होंगे? ● क्या मंडियों और खरीद केंद्रों की व्यवस्थाएँ पहले से बेहतर की जाएंगी? ● क्या प्रसंस्करण और वैल्यू चेन के विस्तार पर समानांतर निवेश होगा?

एक अवसर या केवल नारा?

'समृद्ध किसान-समृद्ध प्रदेश' का नारा तभी सार्थक होगा जब घोषणाएँ फाइलों से निकलकर खेतों तक पहुँचें। पाँच प्रमुख फसलों पर केंद्रित यह पैकेज किसानों को तात्कालिक राहत दे सकता है, परंतु दीर्घकालिक समृद्धि के लिए प्रसंस्करण, निर्यात, भंडारण और मूल्य स्थिरीकरण तंत्र को समान प्राथमिकता देनी होगी।

किसान के लिए यह वर्ष वास्तव में निर्णायक हो सकता है-यदि सरकार पारदर्शिता, समयबद्धता और संवाद की नीति अपनाती है। किसान अब केवल घोषणाएँ नहीं, परिणाम देखना चाहते हैं।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक **विजय कुमार बोन्द्रिया** द्वारा 14, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल से प्रकाशित एवं कृषक जगत 14, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, भोपाल (मध्य प्रदेश) से मुद्रित, **सम्पादक : सुनील गंगराड़े,** फोन : 0755-4248100, 2554864, फैक्स : 0755-2571449. E-mail-info@krishakjagat.org इस अंक का मूल्य रु. 12/- वार्षिक शुल्क रु. 600/-.भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक कार्यालय का पंजीयन क्रमांक 1832/57

कृषक जगत
संस्थापक : स्व. माणिकचन्द्र बोन्दिया - स्व. सुरेशचन्द्र गंगराड़े

अमृत जगत

जिसने अहंकार छोड़ दिया वे भवसागर तर गया।

- योग वशिष्ठ

होली के रंग को बदरंग न बनाएं

वैसे तो भारत के सभी त्यौहार उल्लास, उमंग और खुशियों से लबरेज होते हैं लेकिन होली ही एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हर आयु वर्ग के लोग पूरी मस्ती से रंगों में सरोबार हो जाते हैं। होली भारतीय संस्कृति का वह उल्लासपूर्ण पर्व है, जिसमें रंग केवल चेहरे पर नहीं, बल्कि मन पर भी लगाए जाते हैं। यह पर्व वसंत के आगमन, प्रकृति के नवजीवन और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। फाल्गुन पूर्णिमा की संध्या से लेकर देर रात्रि में होलिका दहन किया जाता है जो हमें बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश देती है। अगले दिन रंगोत्सव के रूप में प्रेम, सौहार्द्र और उत्साह के साथ समूचा देश रंगमय हो जाता है। किंतु विडंबना यह है कि जिस पर्व का उद्देश्य मन का मैल धोकर आपस में प्रेम और सौहार्द्र का परिचय देना होता है, वही कभी-कभी असंयम, प्रदूषण और अव्यवस्था के कारण बदरंग हो जाता है। होली वास्तव में रंगों का ही त्यौहार और खेल नहीं बल्कि यह सामाजिक भेदभाव मिटाने और रिश्तों की कड़वाहट को दूर करने का भी एक सुअवसर प्रदान करता है। लोकगीतों, फाग और हास्य-व्यंग्य की परंपरा समाज को खुलकर हँसने और जुड़ने का अवसर प्रदान करती है। भारतीयता की इस विशाल विरासत और परंपरा में होली प्रेम और मेल-मिलाप का पर्याय भी बन जाता है लेकिन जब स्वार्थ, वैमनस्यता और संकुचित सोच के कारण कभी-कभी इस पर्व का मूल संदेश गौण हो जाता है। होली में पहले प्राकृतिक रंगों का ही उपयोग किया जाता रहा है तथा टेसू (पलाश) के फूलों से केसरिया रंग, हल्दी से पीला और चुकंदर से गुलाबी रंग बनाया जाता था। लेकिन पिछले दो-तीन दशकों से बाजार में मिलने वाले सस्ते रासायनिक रंगों ने होली के स्वरूप को प्रभावित किया है। इन रंगों में सीसा, क्रोमियम और अन्य हानिकारक तत्व मिलाए जाते हैं जो त्वचा रोग, एलर्जी, आँखों में जलन और बालों को नुकसान पहुंचाते हैं। बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए ये रासायनिक रंग तो विशेष रूप से हानिकारक होते हैं। आज आवश्यकता है कि हम फिर से उन्हीं सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल रंगों की ओर लौटें। घर में बने गुलाल या विश्वसनीय स्रोत से खरीदे गए हर्बल रंग स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प हैं। हालांकि कुछ वर्षों से प्राकृतिक रंगों और गुलाल से होली खेलने का रिवाज बढ़ रहा है। मध्यप्रदेश में तो वन विभाग हर्बल रंग और गुलाल तैयार कर रियायत कीमतों पर आम जनता को उपलब्ध

करवाता है। आम जनता में भी प्राकृतिक रंगों के प्रति रूचि बढ़ रही है और इसकी लोकप्रियता का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रंग और गुलाल की मांग पूरी नहीं कर पाते हैं। होली में एक ओर जहां प्रेम और सौहार्द्र का वातावरण दिखाई देता है वहीं दूसरी ओर कुछ लोग होली के नाम पर छेड़छाड़, अभद्रता और जबरदस्ती रंग लगाने से बाज नहीं आते जिसके कारण घटित होने वाली ये घटनाएँ समाज के लिए कलंक हैं। 'बुरा न मानो होली है' वाक्य की आड़ में किसी को भी मर्यादा से इतर कोई भी असामाजिक कार्य करने की छूट नहीं दी जा सकती। यह वाक्य किसी को असहज या आहत करने का लाइसेंस नहीं हो सकता। किसी की सहमति के बिना रंग लगाना या मज़ाक करना अनुचित है। परिवार और समाज का दायित्व है कि वह इस दिन विशेष सतर्कता बरते और महिलाओं, बच्चों तथा बुजुर्गों की गरिमा का सम्मान करे। होली में नशे के प्रचलन में वृद्धि हो रही है और नशा करने वालों में सर्वाधिक युवा वर्ग होता है। शराब या अन्य मादक पदार्थों के सेवन से दुर्घटनाएँ होती हैं। विवाद भी होते हैं और कभी-कभी ये तो प्राणघातक भी सिद्ध होते हैं। इससे पूरे उत्सव का वातावरण ही दूषित हो जाता है। होली के अवसर पर जल की अत्यधिक बर्बादी भी एक गंभीर चिंता का विषय हो सकता है। जल संकट से जूझते देश में करोड़ों लीटर पानी केवल मनोरंजन के लिए बहा दिया जाता है। इसलिए कुछ वर्षों से केवल गुलाल से सूखी होली खेलने की परंपरा का प्रचलन बढ़ रहा है। यह न केवल पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी अधिक संयमित है। गुलाल से होली खेलने से पर्व की मर्यादा बनी रहती है और विवाद आदि से भी निजात मिलती है। सोशल मीडिया के इस दौर में अधिकांश लोग अपनी तस्वीर साझा करना चाहते हैं और कभी-कभी अतिउत्साह में या जान-बूझकर विशेषकर महिलाओं/बालिकाओं के चित्र भी वायरल कर देते हैं। किसी की अनुमति के बिना उसकी तस्वीर या वीडियो साझा करना निजता का उल्लंघन है। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखते हुए डिजीटल मर्यादा का पालन करना चाहिए। जिस तरह मकर संक्रान्ति के अवसर पर चीनी मांझा पर प्रतिबंध के बावजूद पतंग उड़ाने के लिए यह मांझा चोरी-छुपे विक्रय किया जाता है और हर साल अनेक घटनाएं चीनी मांझा के कारण होती हैं। इसी प्रकार होली के दौरान हानिकारक रासायनिक रंग बाजारों में खुलेआम विक्रय किये जाते हैं। यहां सबसे अधिक जिम्मेदारी परिवार की होती है, उन्हें ऐसे हानिकारक रासायनिक रंगों को घर में लाने से परहेज करना चाहिए। प्रशासन को भी चाहिए कि वह मिलावटी और हानिकारक रासायनिक रंगों की बिक्री पर रोक लगाए और सुरक्षा के उचित प्रबंध करे। आइए, इस होली में हम संकल्प लें कि प्राकृतिक रंगों और गुलाल का ही उपयोग तथा यथासम्भव जल की भी बचत करेंगे। यदि कोई रंग या गुलाल लगाने से मना करता है तो जबरदस्ती रंग और गुलाल नहीं डालेंगे। नशे से दूर रहेंगे और पर्यावरण की रक्षा करेंगे।

ओरण के अस्तित्व के लिए 'राष्ट्रीय गोसेवा नीति'

● कौशल किशोर

राजस्थान के करीब 41 लाख एकड़ 'ओरण भूमि' पर संकट के बादल छाए हुए हैं। सूबे की सरकार ने जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जालोर और पाली जिले में 'सोलर पार्क' जैसे व्यावसायिक कार्यों के लिए नियमों को ताक पर रखकर सैकड़ों एकड़ ऐसी जमीन का भू-उपयोग बदलकर जनता को विरोध के लिए मजबूर किया है। इस 'ओरण क्षेत्र' को देश के अन्य क्षेत्रों में 'देवभूमि,' 'देवबनी' और 'गोचर' कहा जाता है।

सार्वजनिक उपयोग के कारण इसका नियंत्रण ग्रामसभा के आधीन होता है इसलिए ग्राम पंचायत की सहमति के बिना सरकार इस परिवर्तन के लिए अधिकृत भी नहीं है। ऐसा करने से पहले उतनी ही भूमि गोचर-ओरण के लिए अन्यत्र आवंटित करने का विधान है। इसके विरुद्ध ग्रामसभा प्रस्ताव पारित कर प्रशासन को ज्ञापन देने के साथ धरना-प्रदर्शन व यात्रा निकालकर जन-जागरण और सत्याग्रह करने में लगी है। सरकार और प्रशासन की कोशिशों के बावजूद यह सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसी के साथ 'अरावली संरक्षण आंदोलन' भी सुर्खियों में है।

उच्चतम न्यायालय केन्द्र सरकार की अनुशंसा पर 20 नवम्बर 2025 को अरावली पर्वत की परिभाषा बदल देता है। राजस्थान और गुजरात ही नहीं, बल्कि दिल्ली और हरियाणा में भी जनता इसका विरोध करने लगी है। लगातार बढ़ते इस विरोध को ध्यान में रखकर 27 दिसम्बर को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली

अरावली संरक्षण को लेकर उठे हाल के जनांदोलन ने एक बार फिर चरोखर यानि 'ओरण' और दुधारू पशुओं की अहमियत भी उजागर कर दी है। दरअसल पर्यावरण आसपास की तमाम-ओ-तमाम प्राकृतिक इकाइयों के मिलने से बनता है जिनमें चरोखर और पशु भी शामिल हैं।

अवकाश पीठ ने इस पर स्थगनादेश जारी कर सुनवाई शुरू की, लेकिन सरकार और न्यायालय की मंशा भांपकर आम लोग सार्वजनिक उपयोग की जमीन को बचाने के लिए संघर्ष का बिगुल फूंक चुके हैं। 'अरावली संरक्षण आंदोलन' और 'ओरण क्षेत्र' की रक्षा में लगे समूह एकजुट हो रहे हैं। जन-जागरण के लिए दोनों समूहों की सक्रियता साफ दिखती है। सार्वजनिक उपयोग की भूमि उद्योगपतियों को सौंपने के मामले में सरकार को आने वाले समय में मुश्किलों का सामना करना होगा।

गौरक्षा आंदोलन के प्रवर्तक संत समाज के लोग भी इस जनांदोलन से जुड़कर विरोध दर्ज कर रहे हैं। हालांकि राजसत्ता के सामने इनकी हस्ती भी 1966 से ही 'पब्लिक डोमेन' में रही है। इंदिरा गांधी की सरकार ने देश को आईना दिखाया था। महात्मा गांधी और संघ परिवार से जुड़े धर्मपाल जी की अध्यक्षता में 'राष्ट्रीय पशु आयोग' का गठन कर 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने एक पहल अवश्य शुरू की थी।

उन्नीसवीं सदी में भारत की राजनीतिक स्थिति इतनी खराब थी कि इसे ब्रिटिश उपनिवेश का हिस्सा होना पड़ा था। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर गौहत्या का नया दौर शुरू हुआ। हालांकि गोकशी मुगलों के समय ही जारी थी। अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर कत्लखाने बनाए थे। अंग्रेजी राज में सन् 1808 से 1947 के बीच बाजार को ध्यान में रखकर खोले गए बूचड़खाने की वजह से गाय का मांस और खाल विदेशी बाजार की जरूरतों को भी पूरा करने लगा। हालांकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान के अनुच्छेद 48 में गौहत्या पर प्रतिबंध लगाने का असफल प्रयास अवश्य शुरु हुआ, लेकिन शोषण की यह दास्तान आज भी जारी है। इस नई औपनिवेशिक परंपरा को तोड़ना भारतीय अस्मिता से जुड़ा गंभीर मामला है। गांधी इसे स्वतंत्रता की प्राप्ति से रत्ती भर कमतर नहीं आंकते थे। राजस्थान की स्थानीय संस्कृतियों से इतर पश्चिमी देशों के राजनीतिक दर्शन में वैज्ञानिक तकनीकी की अहम भूमिका है। इसका प्रभाव युद्ध से लेकर प्रकृति के दोहन तक विद्यमान है। इसने शारीरिक श्रम पर आधारित कृषि व गौसेवा के भारतीय दर्शन को बदलकर रख दिया है। गोबर और गोमूत्र जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। रासायनिक खाद और कीटनाशकों की वजह से क्षय हुई भूमि की गुणवत्ता सुधारने में इनकी अहम भूमिका हो सकती है। इक्कीसवीं सदी में 'श्री-अन्न' की पैरवी करने वाला भारत क्या अपनी ही पुरानी कृषि संस्कृति का पुनरुद्धार कर सकेगा? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के क्रम में कई गांठों को खोलने की आवश्यकता है।

आजादी के बाद खेत जोतने में सक्षम बैलों की जगह ट्रैक्टर का इस्तेमाल प्रचलन में आ गया है। कृत्रिम गर्भाधान की तकनीक से दूसरा हमला भी किया गया। बैल और नंदी की जरूरत खत्म होती गई। 'गोचर भूमि' पर इन पशुओं के लिए चारागाह का प्रबंध था। इस मामले में एक और बात नजरंदाज करने योग्य नहीं है। आयुर्वेद में गाय के दूध से बने देसी घी की तुलना अमृत से की गई है। स्वास्थ्य के लिए इसे हानिकारक बताने की राजनीति भी इस कड़ी में शामिल है। इसके पीछे यदि कोई ठोस आधार रहा होता तो अब तक सामने अवश्य आता। यह अमरीकी 'फार्मा लॉबी' और आधुनिक चिकित्सा पद्धति के बीच गठजोड़ को ही दर्शाता है। इस मामले में एक ऐसी 'राष्ट्रीय गोसेवा नीति' की जरूरत है, जो गौ-हत्या रोकने और 'गोचर भूमि' संरक्षण के साथ ही इन सभी समस्याओं को दूर करती हो। कृतज्ञता और सभी का हित गाय के प्रति श्रद्धा का मूल आधार है। 'राष्ट्रीय गोसेवा नीति' के केन्द्र में इन्हें होना चाहिए।

(सप्रेस)

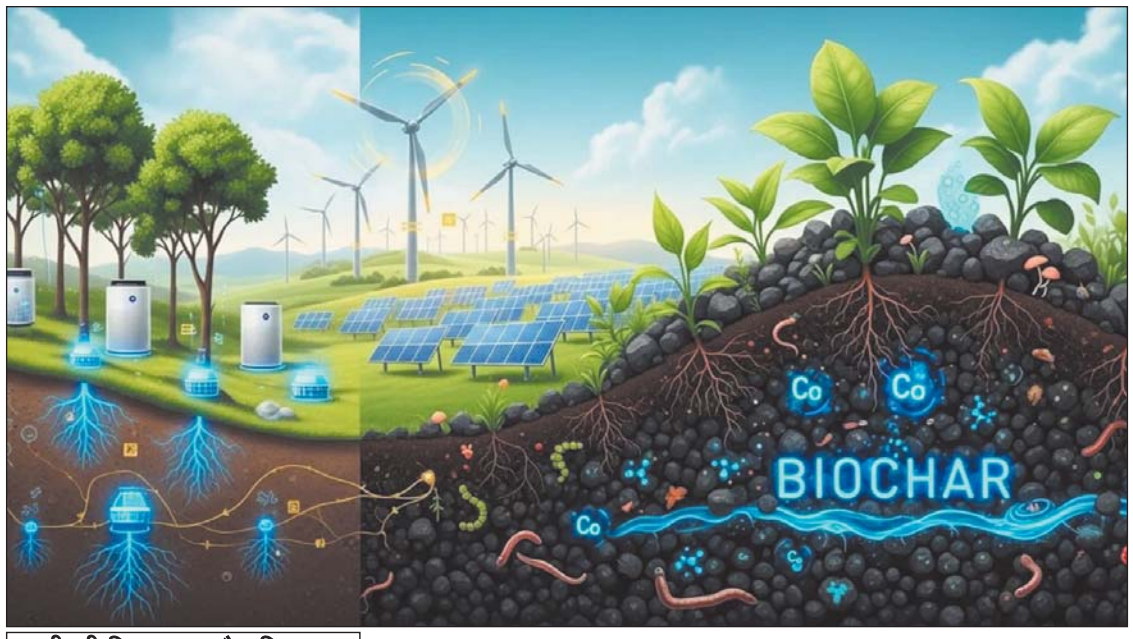

बायोचार कृषि एवं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक नवाचारी समाधान

● श्रीमती रिया ठाकुर, वैज्ञानिक,
● डॉ. आर. के. झाड़े, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख, कृ. वि. केन्द्र, छिंदवाड़ा
● डॉ. अजय हलधर, सहायक प्राध्यापक, रायसोनी यूनिवर्सिटी, साईंखेड़ा
riyath29@gmail.com

आधुनिक कृषि प्रणाली आज जिस संक्रमण काल से गुजर रही है, वह केवल उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि मृदा स्वास्थ्य, पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु परिवर्तन जैसे व्यापक प्रश्नों से भी गहराई से जुड़ी हुई है। हरित क्रांति के पश्चात कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि तो हुई, परंतु इसके साथ-साथ रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और गहन जुताई आधारित खेती के कारण मृदा की जैविक गुणवत्ता में निरंतर गिरावट देखी गई है। मृदा जैविक कार्बन का ह्रास, मृदा संरचना का क्षरण, पोषक तत्वों की उपयोग दक्षता में कमी तथा जल संसाधनों पर बढ़ता दबाव आज वैश्विक कृषि की प्रमुख समस्याओं में शामिल हैं। इन परिस्थितियों में कृषि वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों का ध्यान ऐसी तकनीकों की ओर केंद्रित हुआ है, जो न केवल उत्पादकता बनाए रखें, बल्कि दीर्घकाल में मृदा और पर्यावरण की रक्षा भी करें। इसी संदर्भ में बायोचार एक अत्यंत महत्वपूर्ण, वैज्ञानिक रूप से समर्थित और बहुआयामी समाधान के रूप में उभरा है।

बायोचार को सामान्यतः जैविक अवशेषों से प्राप्त एक स्थिर, कार्बन-समृद्ध पदार्थ के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे सीमित अथवा पूर्णतः अनुपस्थित ऑक्सीजन की दशा में नियंत्रित तापमान पर पायरोलिसिस प्रक्रिया द्वारा निर्मित किया जाता है। यह परिभाषा अपने आप में बायोचार की विशिष्टता को स्पष्ट करती है, क्योंकि यह साधारण जैविक खाद या चारकोल से मूलतः भिन्न है। जहाँ जैविक खाद शीघ्र विघटित होकर अल्पकालिक पोषक तत्व प्रदान करती है, वहीं बायोचार अत्यधिक स्थिर होता है और मृदा में सैकड़ों वर्षों तक बना रह सकता है। इसी स्थायित्व के कारण बायोचार को कार्बन स्थिरीकरण की एक प्रभावी तकनीक माना जाता है, जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाकर मृदा में सुरक्षित रूप से संग्रहित करने में सक्षम है।

बायोचार निर्माण की प्रक्रिया

बायोचार बनाने की प्रमुख विधियाँ

धीमी पायरोलिसिस
- कम तापमान और अधिक समय
- तापमानः 300-500
- अधिक मात्रा में बायोचार प्राप्त होता है।

तेज पायरोलिसिस
- अधिक तापमान और कम समय
- तापमान : 500-700
- बायो-ऑयल अधिक, बायोचार कम

गैसीफिकेशन
- आंशिक ऑक्सीजन की उपस्थिति
- ऊर्जा उत्पादन के साथ बायोचार उप-उत्पाद के रूप में

पारंपरिक ग्रामीण विधियाँ
- गड्ढा विधि
- ड्रम/भट्टी विधि
- कम लागत, छोटे किसानों हेतु उपयुक्त

ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो बायोचार आधारित मृदा प्रबंधन की अवधारणा पूर्णतः आधुनिक नहीं है। अमेजन बेसिन की प्रसिद्ध 'टेरा प्रेटा' मिट्टियाँ इस बात का प्रमाण हैं कि प्राचीन सभ्यताओं ने जैविक अवशेषों को नियंत्रित रूप से जलाकर मृदा में सम्मिलित किया, जिससे मिट्टी की उर्वरता दीर्घकाल तक बनी रही। आधुनिक वैज्ञानिक अध्ययनों ने यह सिद्ध किया है कि इन मिट्टियों में उच्च जैविक कार्बन, बेहतर जल धारण क्षमता और असाधारण सूक्ष्मजीव विविधता पाई जाती है। यह तथ्य बायोचार के दीर्घकालिक मृदा सुधार प्रभाव को ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दोनों स्तरों पर प्रमाणित करता है।

बायोचार की प्रभावशीलता मुख्यतः उसके भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों के संयुक्त प्रभाव का परिणाम होती है। भौतिक दृष्टि से बायोचार अत्यधिक छिद्रयुक्त होता है, जिसके कारण इसका सतह क्षेत्रफल अत्यंत अधिक होता है। यह छिद्रयुक्त संरचना मिट्टी में वायु और जल के संतुलन को सुधारती है, जिससे जड़ों का विकास बेहतर होता है। विशेष रूप से भारी मिट्टियों में यह वायुसंचार को बढ़ाता है, जबकि रेतीली मिट्टियों में जल धारण क्षमता को उल्लेखनीय रूप से सुधारता है। इस प्रकार, बायोचार विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में उनकी विशिष्ट समस्याओं के समाधान के रूप में कार्य कर सकता है।

रासायनिक गुणों की दृष्टि से बायोचार में उच्च कार्बन सामग्री पाई जाती है, जो इसे विघटन के प्रति प्रतिरोधी बनाती है। इसके अतिरिक्त, बायोचार की सतह पर नकारात्मक आवेश उपस्थित होते हैं, जो पोषक तत्वों को अवशोषित कर उन्हें मृदा में बनाए रखने में सहायक होते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जैसे प्रमुख पोषक तत्वों का अपवाह कृषि प्रणालियों में एक गंभीर समस्या है, जिससे न केवल उर्वरकों की दक्षता घटती है, बल्कि जल प्रदूषण भी बढ़ता है। बायोचार इस अपवाह को कम कर पोषक तत्वों की उपलब्धता को नियंत्रित रूप से बनाए रखता है, जिससे फसलों को लंबे समय तक पोषण मिलता है।

मृदा जैविक कार्बन की दृष्टि से बायोचार का महत्व विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वैश्विक स्तर पर यह स्वीकार किया जा चुका है कि मृदा जैविक कार्बन न केवल मृदा उर्वरता का आधार है, बल्कि जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। सामान्य जैविक पदार्थ कुछ वर्षों में विघटित हो जाते हैं, जबकि बायोचार एक स्थिर कार्बन रूप है, जो सैकड़ों वर्षों तक मृदा में बना रह सकता है। इस दीर्घकालिक स्थिरता के कारण बायोचार को 'कार्बन सिंक' के रूप में देखा जाता है, जो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को स्थायी रूप से मृदा में स्थानांतरित करने में सक्षम है।

कृषि उत्पादन प्रणाली में बायोचार का प्रभाव केवल मृदा गुणों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह फसल उत्पादकता और संसाधन उपयोग दक्षता पर भी प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। विभिन्न फसलों पर किए गए प्रयोगों से यह स्पष्ट हुआ है कि बायोचार के प्रयोग से फसलों की जड़ वृद्धि, जल उपयोग दक्षता और पोषक तत्व अवशोषण क्षमता में सुधार होता है। विशेषकर वर्षा-आधारित और शुष्क क्षेत्रों में, जहाँ जल की उपलब्धता एक सीमित कारक होती है, बायोचार का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। इससे न केवल उपज में वृद्धि होती है, बल्कि फसलों की जल तनाव सहनशीलता भी बढ़ती है।

जैविक और प्राकृतिक खेती प्रणालियों में बायोचार की भूमिका और अधिक रणनीतिक हो जाती है। प्राकृतिक खेती का मूल दर्शन रसायन-मुक्त, जीवित और आत्मनिर्भर मिट्टी पर आधारित है। बायोचार इस दर्शन के अनुरूप एक संरचनात्मक घटक के रूप में कार्य करता है। जीवामृत, घनजीवामृत और अन्य जैविक इनपुट्स के साथ मिलकर यह मृदा में एक स्थायी जैविक ढांचा निर्मित करता है, जो दीर्घकाल तक उत्पादकता को बनाए रखता है। इस संदर्भ में बायोचार को केवल एक इनपुट न मानकर प्राकृतिक खेती की आधारशिला के रूप में देखा जाना चाहिए।

पर्यावरणीय स्तर पर बायोचार के लाभ बहुआयामी हैं। यह ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में सहायक है, विशेषकर नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसों के संदर्भ में। इसके अतिरिक्त, कृषि अपशिष्टों का बायोचार में रूपांतरण पराली जलाने जैसी गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में, जहाँ प्रतिवर्ष करोड़ों टन कृषि अवशेष उत्पन्न होते हैं, बायोचार तकनीक अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण और मृदा सुधारकृतीनों के लिए एकीकृत समाधान प्रदान करती है।

हालाँकि, बायोचार के व्यापक उपयोग के मार्ग में कुछ व्यावहारिक और वैज्ञानिक चुनौतियाँ भी विद्यमान हैं। विभिन्न कच्चे पदार्थों से निर्मित बायोचार की गुणवत्ता में भिन्नता, उत्पादन प्रक्रिया का मानकीकरण, तथा विभिन्न मृदा-जलवायु परिस्थितियों में इसके दीर्घकालिक प्रभावों की सीमित जानकारी प्रमुख चुनौतियाँ हैं। अनुसंधान में इन पहलुओं पर गहन अध्ययन की आवश्यकता है, ताकि स्थान-विशिष्ट और फसल-विशिष्ट अनुशंसाएँ विकसित की जा सकें।

समग्र रूप से यह कहा जा सकता है कि बायोचार केवल एक मृदा संशोधक नहीं, बल्कि कृषि, पर्यावरण और जलवायु विज्ञान के संगम पर स्थित एक रणनीतिक नवाचार है। इसकी वैज्ञानिक समझ, तकनीकी परिष्कार और नीति-स्तरीय समर्थन के माध्यम से इसे सतत कृषि प्रणालियों का अभिन्न अंग बनाया जा सकता है। भविष्य में, कार्बन क्रेडिट, जलवायु-स्मार्ट कृषि और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण की अवधारणाओं के साथ बायोचार का एकीकरण न केवल किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने में भी निर्णायक भूमिका निभाएगा।

जैविक दृष्टि से बायोचार को मृदा सूक्ष्मजीवों के लिए एक आदर्श आवास माना जाता है। इसकी छिद्रयुक्त संरचना लाभकारी जीवाणुओं, कवकों और माइकोराइजा के लिए सुरक्षित आश्रय प्रदान करती है। यह सूक्ष्मजीव मृदा में पोषक तत्व चक्रण, जैविक पदार्थ विघटन और पौधों की पोषक तत्व अवशोषण क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार, बायोचार अप्रत्यक्ष रूप से मृदा जैविक गतिविधि को सुदृढ़ कर फसल उत्पादकता को बढ़ाता है।

ऑनलाईन सदस्यता के लिए लॉग इन करें
www.krishakjagat.org

आधुनिक समय की लाभकारी फसल ड्रैगन फ्रूट की खेती

● संदीप कुमार शर्मा (कृषि मौसम वैज्ञानिक)
● डॉ. संजय सिंह (वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी)
● वंशिका तिवारी (कृषि स्नातक)
जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र, रीवा

ड्रैगन फ्रूट एक प्रकार का विदेशी फल होता है सिर्फ किसानों की आमदनी को दोगुना करती है बल्कि इसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व भी पाए जाते हैं आकर्षक दिखने के कारण इस फल की बाजार में काफी ज्यादा मांग रहती है। भारत में इसकी खेती की जाती है जिसे ड्रैगन फ्रूट के नाम से जाना जाता है विभिन्न प्रकार के शहरी उपभोक्ता जो मधुमेह कार्डियो वैस्कुलर और अन्य तनाव संबंधी बीमारियों से पीड़ित हैं और प्राकृतिक उपचार को प्राथमिकता देते हैं ड्रैगन फ्रूट उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है।

ड्रैगन फ्रूट, हिलोकेरस केक्टेसिया परिवार से संबंधित है। इसे होनोलुलु रानी व पिताया फल के नाम से भी जाना जाता है। यह संतरा, आम, पपीता, केला, सेब आदि की तुलना में अधिक पौष्टिक और फायदेमंद फल है। ड्रैगन फ्रूट बाहर से अनन्नास की भांति दिखाई देता है, लेकिन अन्दर से गूदा सफेद और काले छोटे-छोटे बीजों से भरा हुआ नाशपाती या कीवी की तरह होता है। इस आकर्षक एवं रहस्यमय फल का रंग लाल-गुलाबी होता है। इसकी त्वचा में हरे रंग की पंक्तियां होती हैं, जो ड्रैगन की तरह दिखाई देती हैं इसलिए इसको ड्रैगन फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। ड्रैगन फ्रूट ज्यादातर मैक्सिको और मध्य एशिया में पाया जाता है। यह फल खाने में तरबूज की तरह मीठा होता है।

बीते हुए 3 से 4 साल में जलवायु में काफी परिवर्तन आया है, सूखा पड़ने की स्थिति में भी खराब मिट्टी में भी हो सकता है ड्रैगन फ्रूट में हीलिंग के अच्छे गुण पाए जाते हैं यही कारण है की पौधे की कीमत बाजार में रु. 60 से लेकर रु. 200 तक होती हैं ड्रैगन फ्रूट की कीमत पौधों के पुराने होने पर निर्भर करती है जितना ज्यादा पुराना पौधा होता उसकी कीमत इतनी ही ज्यादा होगी 3 साल पुराने पौधे पर लगाने पर आपको जल्दी उत्पादन मिलने लगेगा।

ड्रैगन फ्रूट के मुख्य प्रकार

बाहरी रंग और गूदे के आधार पर यह फल मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है:

- सफेद गूदा वाला, लाल रंग का फल
- लाल गूदा वाला, लाल रंग का फल
- सफेद गूदा वाला, पीले रंग का फल पोषक तत्व

विदेशी फल है ड्रैगन फ्रूट

ड्रगन फ्रूट भारतीय फल नहीं है, लेकिन इसके लाजवाब स्वाद और लाभकारी फायदों के कारण भारत में भी इसकी मांग काफी बढ़ गयी है। यही वजह है कि हमारे देश में पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में इसका सर्वाधिक उत्पादन किया जा रहा है। ड्रैगन फ्रूट का उपयोग ताजे फल के रूप में करने के साथ-साथ रस, जैम तथा आइसक्रीम के रूप में भी किया जाता है। यह फल खाने में तो स्वादिष्ट लगता ही है, इसके अलावा यह अनेक गंभीर रोगों को ठीक करने की क्षमता भी रखता है।

जलवायु

ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए उष्णकटिबंधीय मौसम की स्थिति बेहतर होती है। ड्रैगन फ्रूट की खेती 50 सेमी की वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भी हो सकती है। इसके लिए 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है। ड्रैगन फ्रूट की फसल के लिए तेज धूप की जरूरत नहीं होती है।

मृदा

ड्रैगन फ्रूट की खेती में अधिकतर बलुई दोमट या मिट्टी की दोमट आवश्यकता हो सकती है। ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए रेतीली मिट्टी बेहतर होती है। इसकी खेती करने के खेत की अच्छे से जुताई करें और खर पतवार से मुक्त हो। इसकी खेती के लिए मिट्टी का पीएम मान 5.5 से 7 के बीच हो। इसके साथ ही खेत तैयार करते वक्त ही खेत में क्षेत्रफल के हिसाब से जैविक खाद डालें।

भूमि की तैयारी

खेत अच्छी तरह से जुताई किया हुआ हो, कीट-पतंगों व खरपतवारों से मुक्त हो। भूमि में 20 से 25 टन प्रति हेक्टर की दर से अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद अथवा कम्पोस्ट मिला दें।

ड्रैगन फ्रूट की कैसे करें रोपाई

ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए मूल रूप से दो तरीके हैं। पहला ड्रैगन को सीधे चाकू से काटकर दो भागों में बांटकर उसके अंदर से काले बीज निकाल कर खेती के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। पर इसस पौधे उगाने में समय लगता है इसलिए कमर्शियल खेती के लिए यह उचित नहीं है। दूसरा तरीका है इसके कटिंग को खेत में लगाना। ड्रैगन फ्रूट की रोपाई से दो दिन पहले मदर ड्रैगन पौधों को 20 सेमी की लंबाई में काट लें और लगाने से पहले इस कटिंग पीस को सूखे गोबर, ऊपरी मिट्टी और रेत के मिश्रण के साथ 1:1:2 के अनुपात में एक बर्तन में रखें। इन कटे हुए टुकड़ों से धूप से बचें।

प्रत्येक पौधे को उनके बीच 2×2 मीटर की जगह रखें और 60×60× 60 सेमी आकार के गड्ढे में लगाएं। साथ ही इस गड्ढे को 100 ग्राम सुपर फास्फेट खाद से भर दें। 1 एकड़ भूमि में लगभग 1700 ड्रैगन फ्रूट के पौधे हैं। पौधे के समुचित विकास और विकास के लिए कांक्रीट या लकड़ी के स्तंभों का सहारा लें।

अंतरण

अधिक उत्पादन के लिए पौधे से पौधे एवं पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी 2×2 मीटर रखते हैं। गड्ढे का आकार 60×60×60 सें.मी. रखते हैं।

पादप सघनता

ड्रैगन फ्रूट से अधिकतम उत्पादन लेने के लिए एक हेक्टर भूमि में लगभग 277 पौधे लगाए जा सकते हैं। ट्रिमिंग व प्रूनिंग पौधों की सीधी वृद्धि एवं विकास के लिए इनको लकड़ी व सीमेंट के खंभों से सहारा प्रदान करें। अपरिपक्व पादप तनों को इन खंभों से बांधकर, पार्श्विक शाखाओं को सीमित रखते हुए दो से तीन मुख्य तनों को बढ़ने के लिए छोड़ दें। इसके बाद इसके ढांचे को गोलाकार रूप में सुरक्षित कर लें।

खाद एवं उर्वरक

अधिक उत्पादन लेने के लिए प्रत्येक पौधे को अच्छी सड़ी हुई 10 से 15 कि.ग्रा. गोबर या कम्पोस्ट खाद दें। इसके अलावा लगभग 250 ग्राम नीम की खली, 30-40 ग्राम फोरेट एवं 5-7 ग्राम बाविस्टीन प्रत्येक गड्ढे में अच्छी तरह मिला देने से पौधों में मृदाजनित रोग एवं कीट नहीं लगते हैं। 50 ग्राम यूरिया, 50 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट तथा 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश का मिश्रण बनाकर पौधों को फूल आने से पहले अप्रैल में फल विकास अवस्था तथा जुलाई-अगस्त और फल तुड़ाई के बाद दिसबंर में दें।

सिंचाई

ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, माइक्रो जेट और बेसिन इरिगेशन जैसी नवीनतम तकनीक में कई सिंचाई प्रणालियाँ उपलब्ध हैं लेकिन ड्रैगन फ्रूट प्लांट को अन्य फलों की खेती की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है।

ड्रैगन फ्रूट के पौधे लगाने के एक साल बाद फल लगने शुरू हो जाते हैं। फूल आने के एक महीने बाद, ड्रैगन फ्रूट कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं। अपरिपक्व ड्रैगन फ्रूट में चमकीले हरे रंग की त्वचा होती है। कुछ दिनों बाद फलों का छिलका गहरे हरे से लाल रंग का हो जाता है। ड्रैगन फ्रूट की कटाई का बेहतर समय फल के त्वचा का रंग बदलने के 3 से 4 दिन बाद होता है।

कीट एवं व्याधियां

सामान्यत: ड्रैगन फ्रूट में कीट और व्याधियों का प्रकोप कम होता है। फिर भी इसमें एंथ्रेक्नोज रोग व थ्रिप्स कीट का प्रकोप देखा गया है। एंथ्रेक्नोज रोग के नियंत्रण के लिए मैन्कोजेब दवा के घोल का 0.25 प्रतिशत की दर से छिड़काव करें। थ्रिप्स के लिए एसीफेट दवा का 0.1 प्रतिशत की दर से छिड़काव करें।

तुड़ाई

प्राय: ड्रैगन फ्रूट प्रथम वर्ष में फल देना शुरू कर देता है। सामान्यत: मई और जून में फूल लगते हैं तथा जुलाई से दिसंबर तक फल लगते हैं। पुष्पण के एक महीने बाद फल तुड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। इस अवधि के दौरान इसकी 6 तुड़ाई की जा सकती है। ड्रैगन फ्रूट के कच्चे फल हरे रंग के होते हैं, जो पकने पर लाल रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। फलों की तुड़ाई का सही समय रंग परिवर्तित होने के तीन-चार दिनों बाद का होता है। फलों की तुड़ाई दरांती या हाथ से की जाती है।

उपज

ड्रैगन फ्रूट का पौधा एक सीजन में 3 से 4 बार फल देता है। प्रत्येक फल का वजन लगभग 300 से 800 ग्राम तक होता है। एक पौधे पर 50 से 120 फल लगते हैं। इस प्रकार इसकी औसत उपज 5 से 6 टन प्रति एकड़ होती है।

ड्रैगन फ्रूट के प्रति 100 ग्राम ताजे फल में पाए जाने वाले प्रमुख पोषक तत्व

पोषक तत्व	मात्रा	पोषक तत्व	मात्रा
नमी	85.3 प्रतिशत	विटामिन 'ए'	0.01 मि.ग्रा
प्रोटीन	1.10 ग्राम	नियासिन	2.80 मि.ग्रा
वसा	9.57 मि.ग्रा.	कैल्शियम	10.20 मि.ग्रा
क्रूड फाइबर	1.34 मि.ग्रा.	आयरन	3.37 मि.ग्रा
ऊर्जा	67.70 कि. कैलोरी	मैग्नीशियम	38.90 मि.ग्रा
कार्बोहाइड्रेट	11.2 मि.ग्रा.	फास्फोरस	27.75 मि.ग्रा
ग्लूकोज	5.70 मि.ग्रा.	पोटेशियम	272.0 मि.ग्रा
फ्रक्टोज	3.20 मि.ग्रा.	सोडियम	8.90 मि.ग्रा
सोरबिटोल	0.33 मि.ग्रा.	जिंक	0.35 मि.ग्रा
विटामिन 'सी'	3.00 मि.ग्रा		

ड्रैगन फ्रूट के स्वास्थ्य लाभ

- ड्रैगन फ्रूट फल में कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने की क्षमता होती है।
- शुगर डायबिटीज के रोगियों के लिए या काफी ज्यादा लाभदायक होता है।
- ड्रैगन फ्रूट फाइबर युक्त होता है जो आपके शरीर में आवश्यक पोषक तत्व की कमियों को पूरा करता है।
- इसका सेवन करने से कार्डियोवैस्कुलर रोग होने का खतरा कम हो जाता है।
- हार्ट अटैक जैसे गंभीर रोगों से भी बचा जा सकता है।
- ड्रैगन फ्रूट में एंटीऑक्सीडेंट गुड़ की भरपूर मात्रा उपलब्ध होती है ।
- पोटेशियम और विटामिन की भी प्रचुर मात्रा ड्रैगन फ्रूट के फल में उपलब्ध होती है।

पशुपालन - 'सुरक्षा भी, उत्पादन भी'

● वंशिका तिवारी ● डॉ. अखिलेश कुमार
● डॉ. अनिल कुमार गिरी ● डॉ. संजय सिंह
कृषि विज्ञान केंद्र, रीवा

सर्दी केवल ठंड का मौसम नहीं है। यह कोहरा, पाला, ठंडी हवाएँ और बढ़ी हुई नमी लेकर आती है, जो पशुओं के लिए बड़ी चुनौती बनती हैं। यदि इस मौसम में सही प्रबंधन न किया जाए तो दूध उत्पादन घटता है, पशुओं का वजन कम होता है और निमोनिया, दस्त तथा खुरपका-मुंहपका जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।

सर्दियों की प्रमुख चुनौतियाँ

● रात में तापमान 5 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिरना
● सुबह घना कोहरा
● खुले या अर्ध-खुले शेड में ठंडी हवाओं का प्रभाव
● अत्यधिक ठंडा पानी

इन परिस्थितियों में पशुपालन के लिए विशेष सावधानी आवश्यक है।

गाय-भैंस पालन : आवास व्यवस्था

अधिकतर पशु खुले या अर्ध-खुले शेड में रखे जाते हैं। सर्दियों में निम्न बातों का ध्यान रखें:

● शेड उत्तर-दक्षिण दिशा में हो।
● पश्चिम और उत्तर दिशा से तिरपाल या बोरी द्वारा ढकाव करें।
● फर्श ऊँचा और पूरी तरह सूखा रखें।
● पुआल या भूसे की मोटी बिछावन करें।
● रात में ठंडी हवा का प्रवेश पूरी तरह रोकें।
● गीलापन और ठंडी हवा मिलकर निमोनिया का खतरा बढ़ाते हैं।

विशेष आहार (ऊर्जा वृद्धि)

ठंड में पशु शरीर की गर्मी बनाए रखने के लिए अधिक ऊर्जा खर्च करता है, इसलिए संतुलित और ऊर्जा युक्त आहार आवश्यक है।

● गेहूँ भूसा और चना भूसा
● हरा चारा जैसे बरसीम और जई
● मक्का (ऊर्जा का मुख्य स्रोत)
● सरसों या सोयाबीन खली (प्रोटीन)
● चोकर
● मिनरल मिक्सचर 50 से 60 ग्राम प्रतिदिन
● नमक 30 ग्राम प्रतिदिन

दूध देने वाली गाय या भैंस को प्रत्येक एक लीटर दूध पर लगभग 400 ग्राम अतिरिक्त दाना दें।

पानी का प्रबंधन

● सुबह 10 बजे के बाद पानी पिलाएँ।
● अत्यधिक ठंडा पानी न दें।
● यदि संभव हो तो हल्का गुनगुना पानी दें।
● अत्यधिक ठंडा पानी भूख कम कर देता है और दूध उत्पादन घटा सकता है।

सामान्य रोग और रोकथाम

सर्दियों में निम्न रोग अधिक देखे जाते हैं:

● निमोनिया
● खुरपका-मुंहपका
● गलघोटू
● थनैला

रोकथाम के लिए

● समय पर टीकाकरण कराएँ।
● प्रत्येक छह माह में कृमिनाशक दवा दें।
● खाँसी, नाक बहना या सुस्ती जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें।

वैज्ञानिक सलाह के लिए कृषि विज्ञान केंद्र, रीवा से संपर्क किया जा सकता है, जहाँ संतुलित आहार और रोग नियंत्रण संबंधी प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन उपलब्ध है।

बकरी पालन : विशेष सावधानी

बकरी पालन तेजी से बढ़ रहा है, परंतु सर्दियों में बकरी के बच्चे सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं।

● शेड व्यवस्था
● ऊँचे और सूखे स्थान पर शेड बनाएँ।
● बाँस या लकड़ी का फर्श रखें ताकि नमी से बचाव हो।
● बच्चों को अलग और गर्म स्थान पर रखें।
● सीधी ठंडी हवा से बचाव करें।

आहार प्रबंधन

● चना या अरहर का भूसा
● बरसीम तथा अन्य हरी पत्तियाँ
● मक्का, चोकर और खली का मिश्रण
● मिनरल मिक्सचर

सर्दियों में वजन और रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए ऊर्जा युक्त दाना आवश्यक है।

सर्दियों में उत्पादन घटने के प्रमुख कारण

कारण	परिणाम
ऊर्जा की कमी	दूध उत्पादन कम
ठंडी हवा	निमोनिया
गीला फर्श	संक्रमण
ठंडा पानी	भूख में कमी

रोग नियंत्रण

● पीपीआर का टीकाकरण
● एंटरोटॉक्सिमिया का टीकाकरण
● समय पर कृमिनाशक दवा
● दस्त, कमजोरी या सुस्ती दिखने पर तुरंत उपचार

सर्दियों में बकरी के बच्चे विशेष देखभाल की मांग करते हैं।

धूप का महत्व

सुबह 9 से 11 बजे की धूप अत्यंत लाभकारी होती है :

● विटामिन डी की प्राप्ति
● रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि
● शरीर की प्राकृतिक गर्माहट

निष्कर्ष

सर्दियाँ चुनौतीपूर्ण अवश्य हैं, परंतु सही प्रबंधन से यही मौसम लाभकारी बन सकता है।

● सुरक्षित और सूखा शेड
● ऊर्जा युक्त संतुलित आहार
● समय पर टीकाकरण
● नियमित निरीक्षण

'स्वस्थ पशु, मजबूत किसान और समृद्ध विंध्य यही सफल पशुपालन की पहचान है।'

राज्यपाल ने मुख्यमंत्री दुधारू पशुप्रदाय योजना की समीक्षा की

भोपाल (कृषक जगत)। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा है कि मुख्यमंत्री दुधारू पशुप्रदाय योजना का उद्देश्य प्रदेश के सबसे गरीब परिवारों के जीवन में खुशहाली लाना है। उन्होंने निर्देश दिए कि योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, तत्परता और संवेदनशीलता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। गरीब हितग्राहियों के हितों से किसी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

लोकभवन में आयोजित बैठक में पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग की इस योजना की समीक्षा की गई। बैठक में पशुपालन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री लखन पटेल सहित जनजातीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री दीपक खांडेकर, राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, प्रमुख सचिव पशुपालन एवं डेयरी विकास श्री उमाकांत उमराव एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

किनके लिए है योजना?

यह योजना विशेष रूप से अति पिछड़ी पीवीटीजी जनजातियों–बैगा, भारिया और सहरिया के लिए लागू की जा रही है। राज्यपाल ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में पीवीटीजी जनसंख्या है, उन सभी को योजना के दायरे में शामिल किया जाए।

किसानों और दुग्ध उत्पादकों के लिए महत्वपूर्ण बातें

- पशु वितरण की सामुदायिक निगरानी की व्यवस्था की गई है।
- दुग्ध समितियों द्वारा महीने में तीन निश्चित तिथियों पर (हर 10 दिन में) दूध भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।
- दूध के दाम में 2 से 8.50 रुपये प्रति लीटर तक वृद्धि की गई है।
- चयनित हितग्राहियों को पशु वितरण से पहले 3 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- पशु वितरण के बाद 21 दिन, 3 माह और 6 माह पर समीक्षा की जाएगी।
- पहले चरण में हितग्राही को एक ही दुधारू पशु दिया जाएगा।
- पशु का रखरखाव संतोषजनक पाए जाने पर 3 माह बाद दूसरा पशु देने का प्रावधान।
- जिन गांवों में मिल्क रूट और परिवहन सुविधा उपलब्ध है, वहां प्राथमिकता से लाभ दिया जाएगा, लेकिन जरूरत अनुसार अन्य गांवों को भी शामिल किया जाएगा।

प्रदेश में पर्यावरण-संरक्षण के संदेश के साथ मनेगी होली

गो-काष्ठ आधारित होलिका दहन को बढ़ावा

- **'स्वच्छ और स्वस्थ होली' अभियान के तहत सार्वजनिक होलिका दहन का होगा नि:शुल्क पंजीयन**
- **मुख्यमंत्री डॉ. यादव उत्कृष्ट गो-काष्ठ आधारित होलिका दहन करने वाली संस्थाओं एवं पदाधिकारियों को देंगे प्रशस्ति-पत्र**

भोपाल (कृषक जगत)। इस वर्ष होली पर्व को पर्यावरण-संरक्षण और सामाजिक सद्भाव के संदेश के साथ मनाया जाए। इसके लिए राज्य शासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे आपसी मतभेद भुलाकर भाईचारे, सामाजिक एकता और उल्लास के साथ होली मनाएं। होलिका दहन में लकड़ी के स्थान पर गो-काष्ठ (उपलों) का अधिकाधिक उपयोग करें।

प्रदेश सरकार द्वारा जारी निर्देश अनुसार जनसहयोग एवं सामाजिक सहभागिता के माध्यम से प्रयास किया जाएगा कि होलिका दहन में लकड़ी की जगह गो-काष्ठ का प्रयोग हो। साथ ही, प्राकृतिक एवं हर्बल रंगों से होली खेलने, जल संरक्षण करने तथा पशु-पक्षियों पर रंग न डालने के संकल्प के साथ उत्सव मनाने के लिए नागरिकों को प्रेरित किया जाएगा। जिलों में विभिन्न स्तरों पर आयोजित होने वाले सार्वजनिक होलिका दहन कार्यक्रमों का नि:शुल्क पंजीयन

कराया जाए। यह पंजीयन जिला मुख्यालय, तहसील, नगरीय निकाय एवं पंचायत स्तर पर किया जाएगा। पंजीयन के दौरान आयोजक संस्था की संक्षिप्त जानकारी, पदाधिकारियों के नाम एवं संपर्क विवरण प्राप्त किए जाएंगे।

लकड़ी के स्थान पर करें गो-काष्ठ का उपयोग

जिला स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार कर नागरिकों को गो-काष्ठ आधारित होलिका दहन के लिए प्रेरित किया जाएगा। नगरीय निकायों एवं पंचायत राज संस्थाओं को इस अभियान में सक्रिय रूप से शामिल किया गया है। होलिका दहन के दिन मैदानी अमला सार्वजनिक आयोजनों का निरीक्षण कर लकड़ी के स्थान पर गो-काष्ठ के उपयोग को प्रोत्साहित करेगा। जिन आयोजनों में पूर्ण रूप से गो-काष्ठ आधारित होलिका दहन किया जाएगा, उनको संबंधित अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर कलेक्टर को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। जिलों के कलेक्टर ऐसे आयोजनों का संकलन सुनिश्चित करेंगे।

खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को दिया जाएगा उद्योग का दर्जा : डॉ. यादव

मुख्यमंत्री ग्लोबल काबुली चना कॉन्क्लेव में हुए शामिल

भोपाल/इंदौर(कृषक जगत)। डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश कृषि के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और दलहन एवं तिलहन उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य बन चुका है। उन्होंने घोषणा की कि प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा, जिससे निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

मुख्यमंत्री इंदौर में आयोजित 'ग्लोबल काबुली चना कॉन्क्लेव' को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने निवेशकों से आह्वान किया कि वे प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना में निवेश करें। राज्य शासन द्वारा भूमि, बिजली, पानी और करों में रियायत सहित हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कृषि आधारित उद्योगों और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्षीय रोडमैप तैयार किया है। उन्होंने अगले पांच वर्षों में राज्य का बजट दोगुना करने का लक्ष्य भी दोहराया।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उद्योगपतियों का सम्मान किया। समिट में देश-विदेश के प्रतिनिधि, जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, सांसद श्री शंकर लालवानी, विधायक श्री रमेश मेंदोला तथा श्री गोलू शुक्ला, श्री गौरव रणदीवे, श्री सावन सोनकर, श्री सुमित मिश्रा, श्री जयपाल सिंह चावड़ा, श्री श्रवण चावड़ा, श्री संजय अग्रवाल सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

फोटो गैलरी

मुलाकात

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह से उनके निवास स्थान पर सौजन्य मुलाकात की।

सोलर रथ

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री राकेश शुक्ला ने ऊर्जा भवन में 'सोलर रथ सह मोबाइल बूथ वैन' को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्री मनु श्रीवास्तव भी उपस्थित थे।

मप्र में सिंचाई के 100 हे. रकबे के लक्ष्य को जल्द करेंगे हासिल

भोपाल। किसानों के सूखे खेतों में जब सिंचाई का पानी पहुंचता है तो मिट्टी सोना उगलती है। किसान कल्याण वर्ष 2026 में किसानों की समृद्धि के लिए उनके खेतों में सिंचाई की भरपूर व्यवस्था की जाएगी, जिससे वे वर्ष भर फसलें ले सकें। सिंचाई का रकबा बढ़ाने और हर खेत किसान के खेत तक पानी पहुंचाने के लिये मध्यप्रदेश के बजट 2026-27 में जल प्रदाय योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किये गये है। प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से सिंचित रकबे में निरंतर बढ़ोत्तरी हो रही है। शीघ्र ही प्रदेश में सिंचाई के रकबे को 100 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आगामी वित्तीय वर्ष में जल प्रदाय योजनाओं के लिए जो प्रावधान किये गये हैं, उनमें मुख्य रूप से नर्मदा घाटी विकास के अंतर्गत एन.वी.डी.ए. के सभी बिजली बिलों के लिए 689 करोड़ रुपये, सेंधवा उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना में 500 करोड़ रुपये, सांवेर माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना में 400 करोड़ रुपये, आई.एस.पी. कालीसिंध उद्वहन माइक्रो सिंचाई योजना फेस-2 में 400 करोड़ रुपये, बरगी नहर व्यपवर्तन योजना में 399 करोड़ रुपये, चिंकी बोरास बैराज संयुक्त बहुउद्देशीय माइक्रो सिंचाई परियोजना में 350 करोड़ रुपये, सरदार सरोवर के डूब प्रभावित क्षेत्र का भू-अर्जन तथा अन्य कार्यों पर खर्च के लिये 308 करोड़ रुपये, एन. बी. कम्पनी लि. का निवेश में 303 करोड़ रुपये, खंडवा उद्वहन माइक्रो सिंचाई योजना में 300 करोड़ रुपये, नर्मदा (आई.एस.पी.) पार्वती लिंक परियोजना फेस 3 एवं 4 में 300 करोड़ रुपये, शहीद इलाप सिंह माइक्रो सिंचाई योजना में 300 करोड़ रुपये रुपये के प्रावधान शामिल हैं।

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

इस बार होली गौकाष्ठ वाली

"मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, इस होली पर
आइए, एक पर्यावरण-अनुकूल कदम उठाएं, लकड़ी की जगह **'गौकाष्ठ'** को उपयोग करें। लकड़ी जलाने से पेड़ों की कटाई बढ़ती है, जबकि गौमाता के गोबर से बनी गौकाष्ठ प्राकृतिक, शुद्ध, सुरक्षित और पर्यावरण के लिए बेहतर विकल्प है।
आइए, मिलकर हरियाली बचाएं और स्वच्छ, जिम्मेदार होली मनाएं।"

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

ऑनलाईन सदस्यता के लिए लॉग इन करें
www.krishakjagat.org

राजगढ़ के मोहनपुरा में हुआ कृषि मेला, किसान संवाद

राजगढ़ (कृषक जगत)। राजगढ़ के कृषि धाम मोहनपुरा में 23 से 25 फरवरी तक कृषि सम्मेलन एवं प्रदर्शनी का शुभारंभ कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने किया। कार्यक्रम में भोपाल, बनारस, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और खंडवा से आए कृषि वैज्ञानिकों ने उन्नत तकनीकों की जानकारी दी। तिलहन मेले में कोरोमंडल इंटरनेशनल लि. के एग्रोनॉमिस्ट श्री भास्कर तिवारी (ब्यावरा-राजगढ़) सहित विशेषज्ञों ने उर्वरक प्रबंधन, कीट नियंत्रण और उन्नत बीज चयन पर मार्गदर्शन दिया।

उप संचालक कृषि श्री सचिन जैन ने बताया कि सम्मेलन का उद्देश्य किसानों को नई तकनीक व योजनाओं से जोड़कर आय वृद्धि सुनिश्चित करना है। बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लेकर विशेषज्ञों से सीधे संवाद किया।

सम्मेलन में किसानों की समस्याओं पर वैज्ञानिकों ने समाधान सुझाए-प्याज-लहसुन में पीलापन (पोषक तत्वों की कमी, जलभराव, थ्रिप्स), मसूर में उखटा रोग (बीजोपचार व फसल चक्र), लहसुन में बकड़िया रोग (जल निकासी व फफूंदनाशी), चना-मसूर में फूल-फल गिरना (संतुलित पोषण) तथा सोयाबीन में तना मक्खी व गर्डल बीटल नियंत्रण हेतु समय पर कीटनाशक व फेरोमोन ट्रैप की सलाह दी गई। वेटरनरी कॉलेज मऊ के प्रो. मोहब्बत सिंह जमरा ने बकरी पालन में नस्ल चयन, टीकाकरण व संतुलित आहार की जानकारी दी। **इस अवसर पर सांसद श्री रोडमल नागर, कलेक्टर श्री मिश्रा एवं उपसंचालक श्री जैन कृषक जगत के स्टाल पर पधारे। (चित्र में) विशिष्ट अतिथियों को कृषक जगत की नव वर्ष डायरी प्रकाश दुबे द्वारा भेंट की गई।**

उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग की योजनाएं

पुष्प क्षेत्र विस्तार

प्रोजेक्ट - पुष्प क्षेत्र विस्तार

घटक -खुले पुष्प फसल

उद्देश्य - बागवानी उत्पादन की उन्नति, कृषक संख्या में वृद्धि, आमदनी और पोषाहार सुरक्षा को बढ़ावा देना। गुणवत्ता युक्त पौध सामग्री का उपयोग करते हुये उत्पादकता में सुधार लाना। बागवानी अनुसंधान, तकनीकी को बढ़ावा, विस्तारीकरण, फसलोत्तर प्रबंधन, प्रसंस्करण एवं विपणन आदि को बढ़ावा देना। कृषकों को आमदनी का स्थाई स्रोत उपलब्ध कराना। रोजगार के नवीन अवसरों का सृजन करना। उत्पादन एवं प्रसंस्करण को बढ़ाकर उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर बाजार में उद्यानिकी उत्पादों की उपलब्धता बनाए रखना।

कार्य क्षेत्र- जिला कटनी, सिवनी, बालाघाट, नरसिंहपुर, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, श्योपुर, शिवपुरी, मुरैना एवं भिण्ड।

चयनित फसलें- गेंदा, अफ्रीकन गेंदा, बिजली, एस्टर, एन्युअल क्राइसेंथिमम, पेरिनियल क्राइसेंथिमम।

स्वरूप- परियोजना अंतर्गत खुले पुष्प के लिए निर्धारित इकाई लागत राशि 40 हजार रुपये पर 40 प्रतिशत, अनुदान राशि 16 हजार रुपये देय है।

कृषक की पात्रता - सभी वर्ग के लघु एवं सीमान्त कृषक।

अनुदान की पात्रता - निर्धारित इकाई लागत पर 40 प्रतिशत अनुदान देय है।

हितग्राही चयन की प्रक्रिया - कृषक एमपीएफएसटीएस पोर्टल पर पंजीयन करेगा एवं लक्ष्य जारी होने पर पोर्टल पर ही योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन कर सकेगा। आवेदित कृषकों की पात्रता का परीक्षण पोर्टल पर आवेदन करने के दौरान अपलोडेड दस्तावेजों के माध्यम से उप/सहायक संचालक, उद्यानिकी करेगा। प्रत्येक माह की पहली तारीख को हितग्राहियों का चयन कम्प्यूटरीकृत लॉटरी के माध्यम से राज्य स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जाएगा। आवेदकों की संख्या लक्ष्य से कम होने पर लॉटरी की आवश्यकता नहीं होगी। लॉटरी से चयनित कृषकों की सूची एमपीएफएसटीएस पोर्टल एवं विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी एवं चयनित कृषकों को एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

सम्पर्क : जिले के उप/सहायक संचालक उद्यान, विकासखंड स्तर पर व.उ.वि.अधि./ ग्रा.उ.वि.अधि.

आनलाईन आवेदन- पात्र कृषक एमपीएफएसटीएस पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन के लिए दस्तावेज- कृषक का फोटोग्राफ, आधार कार्ड, खसरा नम्बर/बी 1 की प्रति, बैंक पासबुक एवं जाति प्रमाण-पत्र इत्यादि।

स्रोत : जनसंपर्क विभाग म.प्र. के प्रकाशन 'नई राहें नए अवसर' से उद्धृत।

कार्ड ने बताया कृषि मशीनरी तकनीक का उपयोग

भोपाल (कृषक जगत)। मैनेज द्वारा प्रायोजित एग्री-क्लिनिक एवं एग्री-बिजनेस सेंटर योजना के प्रशिक्षण आयोजन की नोडल एजेंसी सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (कार्ड) ने प्रशिक्षु हितग्राहियों का प्रशिक्षण बुधनी स्थित केंद्रीय कृषि एवं मशीनरी संस्थान एवं पवारखेड़ा कृषि महाविद्यालय में कराया। बुधनी संस्थान में डॉ. ए. के. उपाध्याय, डॉ. रणजीत पवार एवं श्री प्रीतम यादव ने आधुनिक कृषि मशीनों एवं ड्रोन तकनीक पर मार्गदर्शन किया।

पवारखेड़ा कृषि महाविद्यालय में डॉ. विनोद कुमार ने रबी सीजन में लगाए गए गेहूं, चना, सरसों, आलू, बरसीम फसलों की जानकारी दी। महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. पी. के. मिश्रा ने महाविद्यालय में उपलब्ध कृषि तकनीकों की जानकारी दी। प्रशिक्षण के दौरान कृषि विभाग की मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला प्रभारी श्री सुनील कुमार धोटे एवं प्राचार्य कृषि विस्तार प्रशिक्षण केंद्र के श्री यू. के. शुक्ला ने भी जानकारी दी। प्रशिक्षणों का आयोजन कार्ड के डॉ. लालचन्द्र यादव के नेतृत्व में किया गया।

मिलेट्स कृषि मेले में किसानों की सक्रिय भागीदारी

धार (कृषक जगत)। कृषि विभाग ने धार में तीन दिवसीय मिलेट्स मेला आयोजित किया। शुभारंभ अवसर पर विधायक नीना वर्मा ने कृषकों से परम्परागत फसलों के साथ मिलेट्स फसलों के उत्पादन की उपयोगिता बताई। उपसंचालक कृषि श्री ज्ञानसिंह मोहनिया ने कृषक कल्याण वर्ष अंतर्गत जिले में संचालित गतिविधियों पर अवगत कराया। कृषि मेले में मिलेट्स फसलों एवं उनसे बनने वाले व्यंजनों का प्रदर्शन, मिलेट्स फसल गेलरी, मिट्टी परीक्षण की उपयोगिता, उन्नत कृषि यंत्रों का प्रदर्शन, ई टोकन उर्वरक वितरण व्यवस्था के अलावा किसानों से जुड़े विभिन्न विभागों,खाद, बीज, कीटनाशक कंपनियों ने भी स्टाल लगाकर कृषकों को जानकारी दी।

विशेषज्ञों में डॉ अमृतलाल बसेडिया, डॉ. नरेश गुप्ता, डॉ. एस. एस. चौहान,श्री एन. के. तांबे, श्रीमती अंकिता पांडे, श्री अभिषेक अग्रवाल, श्रीमती संगीता तोमर, श्रीमती अंकिता सोलंकी, श्री विवेक बार्चे,श्री बर्मन आदि द्वारा जानकारी साझा की गई। कार्यक्रम में निजी कंपनियों द्वारा कृषकों के बीच प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता रखी गई इनमें कोरोमंडल कंपनी ने सही जवाब देने पर कृषक श्री अशोक भारमल को एक ग्राम सोना देकर सम्मानित किया। मेले में परियोजना संचालक आत्मा श्री त्रिलोक चंद छावनिया, उप परियोजना संचालक आत्मा श्री केएस झणिया, भारतीय किसान संघ के प्रदेश मंत्री श्री राजेन्द्र शर्मा एवं श्री महेश ठाकुर, श्री अमोल पाटीदार, किसान मोर्चा अध्यक्ष श्री ब्रजेन्द सिंह, महामंत्री श्री रतनलाल पाटीदार सहित अन्य अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद थे। नोडल अधिकारी सहायक संचालक कृषि श्री दिलीप सिंह मौर्य ने मेले के सफल आयोजन के लिए सभी का आभार व्यक्त किया।

कामयाब किसान की कहानी

लहसुन प्रसंस्करण ईकाई स्थापित कर, आत्मनिर्भर बने पूरब

नीमच। मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव के नेतृत्व में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के माध्यम से नीमच के युवा उद्यमी श्री पूरबसिंह ने नीमच की कृषि उपज मण्डी चंगेरा के पास में लहसुन प्रसंस्करण ईकाई की स्थापना की हैं। पूरबसिंह ने उद्यानिकी विभाग के मार्गदर्शन में वर्ष 24-25 में योजना का लाभ लेकर लहसुन प्रसंस्करण उद्योग प्रारंभ किया हैं। इस उद्योग में लहसुन की कली निकालकर लहसुन की कली की ग्रेडिंग एवं आकर्षण पेकिंग कर अहमदाबाद विक्रय कर रहे हैं। उनकी इस यूनिट में 7 से 8 स्थानीय महिलाओं को रोजगार मिल रहा हैं। योजना के तहत लहसुन प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए पूरबसिंह को भारतीय स्टेट बैंक शाखा दशहरा मैदान नीमच से

30 लाख रूपये का ऋण मिला हैं। साथ ही शासन की ओर उद्यानिकी विभाग द्वारा उन्हें 10 लाख रूपये का अनुदान भी प्रदान किया गया है।

उल्लेखनीय है, कि कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के मार्गदर्शन में नीमच जिले में पीएमएफएमई योजना के तहत अब तक कुल 205 हितग्राहियों को लाभांवित किया गया है।

संतुलित खेती : समस्या से समाधान की ओर

आज खेती का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग लगातार बढ़ा है। शुरुआत में इनसे बेहतर परिणाम मिले, लेकिन समय के साथ मिट्टी कमजोर होने लगी, नई बीमारियाँ बढ़ीं और कीटों में दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई। नतीजा यह हुआ कि हर नई फसल के साथ रसायनों की मात्रा भी बढ़ती गई और किसान एक ऐसे 'केमिकल कुचक्र' में फँस गया, जहाँ समाधान ही धीरे-धीरे समस्या बनता चला गया।

हर किसान के लिए तुरंत संभव नहीं

अधिकांश किसान इस नुकसान को समझते हैं, फिर भी अत्यधिक रसायनों का उपयोग छोड़ नहीं पाते। कारण स्पष्ट है- उत्पादन घटने का डर और व्यवहारिक विकल्पों की कमी। पूरी तरह जैविक खेती अपनाना हर किसान के लिए तुरंत संभव नहीं होता, क्योंकि आय पर सीधा असर पड़ता है। ऐसे में किसानों द्वारा मिट्टी को बचाने और उत्पादन को स्थिर बनाए रखने के बीच संतुलन की तलाश शुरू हुई, जिसने 'संतुलित खेती' के इस अभियान को जन्म दिया।

मिट्टी पहले जैसी नहीं रही

इसी संतुलन की खोज की झलक मध्यप्रदेश के इटारसी क्षेत्र के सनखेड़ी गाँव के किसान 'गोविन्द चौरे' जी के जीवन में भी साफ तौर पर दिखाई देती है। पाँच एकड़ जमीन पर पारंपरिक फसलें उगाने वाले गोविन्द भी अत्यधिक रासायनिक उत्पादों का इस्तेमाल करते थे। हर साल बार-बार रासायनिक दवाइयों और उर्वरकों के छिड़काव के बावजूद उन्हें लगता था कि यही खेती का एकमात्र रास्ता है। लेकिन धीरे-धीरे उन्हें महसूस होने लगा कि मिट्टी पहले जैसी नहीं रही मानो मिट्टी बंजर होने की तरफ बढ़ रही है।

गोविन्द जी ने विकल्प खोजने शुरू किए, पर पूरी तरह जैविक खेती अपनाना जोखिम भरा लगा। इसी दौरान उन्हें संतुलित खेती के बारे में जानकारी मिली- यह एकमात्र ऐसा तरीका है, जिसमें केमिकल को एक साथ पूरी तरह छोड़ने के बजाय किसान अपनी सुविधा और परिस्थिति के अनुसार धीरे-धीरे कम कर सकता है। संतुलित खेती किसानों को अपनी जरूरत और हालात के अनुसार धीरे-धीरे बदलाव करने की छूट देती है। कई किसानों ने पहले ही सीजन से केमिकल की मात्रा 50 प्रतिशत कम कर दी, फिर भी उत्पादन लगभग पहले जैसा ही बना रहा।

रसायनों की मात्रा कम की

गोविन्द जी ने रसायनों की मात्रा कम की, गैर रासायनिक उपाय जोड़े और खेत की जरूरत के अनुसार पोषण प्रबंधन करना शुरू किया, और पहले जहाँ उत्पादन 15 क्विंटल प्रति एकड़ वही अभी भी 14.5 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ बना रहा। गोविन्द जी का कहना है कि 'संतुलित खेती' उन्हें एक आशा की किरण की तरह लगती है, क्योंकि यह बिना उत्पादन घटाए भविष्य में भी मिट्टी को स्वस्थ रखने का रास्ता दिखाती है। उनका मानना है कि यही तरीका आने वाले समय में किसानों को उत्पादन और मिट्टी की सेहत के बीच संतुलन बनाने में बहुत लाभकारी साबित होगा।

जैविक कार्बन की मात्रा लगभग 1 प्रतिशत

विशेषज्ञ बताते हैं कि 1950 के दशक में भारतीय मिट्टी में जैविक कार्बन की मात्रा लगभग 1 प्रतिशत हुआ करती थी, लेकिन आज यह घटकर अधिकांश इलाकों में केवल 0.3-0.4 प्रतिशत के बीच रह गई है। यह स्तर स्वस्थ और उत्पादक मिट्टी के लिए आवश्यक मानक से काफी नीचे है। चेतावनी यह भी है कि यदि जैविक कार्बन 0.3 प्रतिशत से कम हो गया, तो भूमि की उर्वरता गंभीर रूप से प्रभावित होगी और वह बंजर होने की स्थिति तक पहुँच सकती है। संतुलित खेती इस गिरावट को रोकने का एक व्यवहारिक उपाय बन सकती है।

आज गोविन्द जी जैसे किसान इस बात के उदाहरण बन रहे हैं कि खेती में बदलाव केवल नई तकनीक से ही नहीं, बल्कि सोच में परिवर्तन से भी आ सकता है। जब किसान तात्कालिक लाभ के साथ-साथ मिट्टी के दीर्घकालीन स्वास्थ्य को भी महत्व देने लगता है, तभी वह अन्य व्यवहारिक विकल्पों को खोजता है।

संतुलित खेती दरअसल उसी खोज का परिणाम है एक ऐसा मध्य मार्ग जो वर्तमान की जरूरतों और भविष्य की सुरक्षा दोनों को साथ लेकर चलता है। यह न तो पूरी तरह रसायनों पर निर्भर है और न ही तुरंत सब कुछ बदल देने की मांग करता है, बल्कि धीरे-धीरे उस दिशा में ले जाता है जहाँ खेती लाभकारी भी रहे और मिटटी भी अपने पुराने स्वस्थ स्वरूप में लौटे।

समस्या -समाधान

समस्या : पूसा में विकसित चारा फसलों की किस्मों की जानकारी दें?

समाधान: पूसा ने चारा फसलों के रूप में ज्वार की एकल कटाई एवं बहु कटाई वाली संकर किस्में विकसित की हैं। एकल कटाई वाली प्रजातियाँ है पूसा चरी-6 एवं पूसा चरी-9 और बहु कटाई वाली किस्मों, पूसा चरी-23, पूसा चरी संकर-106, पूसा चरी-615, पूसा चरी-109 हैं। पूसा चरी-106 एवं पूसा चरी-23 पूरे भारत के लिए अनुमोदित है जबकि पूसा चरी-615, पूसा चरी -109 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए अनुमोदित है।

समस्या : पूसा चरी 106 की क्या विशेषता है?

समाधान: पूसा चरी 106 गर्मी एवं खरीफ के मौसम में सिंचित अवस्था में बुवाई के लिए उपयुक्त है। यह बहुकटाई वाली पहली संकर किस्म है जिसकी पत्तियां लम्बे समय तक हरी बनी रहती हैं। तना रसदार व मीठा होता है जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक (8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर) होती है। यह फसल 50-55 दिनों में पहली कटाई के लिए तैयार हो जाती है।

समस्या : जौ की अधिक उपज देने वाली किस्में बताइए?

समाधान: जौ की नवीनतम अधिक उपज वाली प्रजातियां निम्नलिखित हैं। समय से बुआई के लिए डीडब्ल्यूआरबी-92, डीडब्ल्यूआरबी-101 एवं पिछेती बुआई के लिए, डी.डब्ल्यू.आर.बी.-73, डी.डब्ल्यू.आर.बी.-91, बी.एच.-885 हैं।

समस्या : अनाज भंडारण की सस्ती तकनीक क्या है?

समाधान: अनाज में नमी का प्रतिशत- किसान भाई इस बात को अच्छी तरह से जान ले कि खाद्यान्न पदार्थ में कीड़ों की प्रकोप के लिए एक निश्चित प्रतिशत में नमी होना आवश्यक है। अनाज भंडारण के समय 8-10 प्रतिशत या इससे कम कर देने पर खपरा बीटल को छोड़कर किसी भी अन्य कीट का आक्रमण नहीं होता। खपरा बीटल (टोगोडरमा ग्रेनेरियम) कीट 2 प्रतिशत नमी तक भी जिन्दा रहता है, बड़े गोदामों में नमी रोधी संयंत्र लगाना चाहिए। जिससे बरसात में भी नमी नहीं बढ़े। उपलब्ध आक्सीजन- अनाज वायुरोधी भंडारगृह में रखना चाहिए। बीज को जीवित रखने के लिए केवल 1 प्रतिशत आक्सीजन की आवश्यकता होती है तथा कीटों को भी श्वसन हेतु आक्सीजन की आवश्यकता होती है। खपरा बीटल 16.8 प्रतिशत से कम आक्सीजन होने पर आक्रमण नहीं करता है। अर्थात् भंडारण में आक्सीजन कम करके कीड़ों की रोकथाम की जा सकती है। आक्सीजन का प्रसार होने पर कीट अधिक लगते है। तापक्रम- नमी की तरह कीटों के विकास के लिए एक निश्चित तापक्रम की आवश्यकता होती है जो कीटों के अधिक विकास के लिए 28 से 32 डिग्री सेन्टीग्रेड होती है।

निवेदन

समस्या-समाधान स्तंभ में पाठकों से निवेदन है कि अपनी खेती-किसानी संबंधी समस्या कृषि विशेषज्ञों से निराकरण करने हेतु वाट्सएप पर भेजें. एक बार में केवल एक प्रमुख समस्या ही वाट्सएप पर लिखकर भेजें. वाट्सएप हेल्पलाइन नं. 6262166222.

समस्या-समाधान
कृषक जगत 14, इंदिरा प्रेस काम्प्लेक्स,
महाराणा प्रताप नगर, भोपाल (म.प्र.)
फोन-0755-4248100,2554864

किसान भाइयों को कृषि सलाह

गेहूं : कई स्थानों पर गेहूं को खड़ी फसल में ज्यादा नमी के कारण पीलापन दिखाई दे रहा है अतः किसान भाइयों को सलाह है कि NPK 19:19:19 पानी में घुलनशील खाद की 100 ग्राम मात्रा प्रति पम्प की दर से पत्तियों पर छिड़काव करें। पूर्व में बोई गई गेहूं फसल में विभिन्न क्रांतिक अवस्थाओं में सिंचाई करें तथा सिंचाई के बाद शेष बची यूरिया का छिड़काव अवश्य करें। यूरिया का छिड़काव करते समय इस बात का ध्यान रखें की पत्तियों पर पानी न हो तथा यूरिया चिपक न जाये। चूहों की रोकथाम करने के लिए जिंक फास्फाइड दवा को कोई भी खाद्य पदार्थ में अच्छी प्रकार से मिला डाल दें।

चना : चने की फसल में फली आना प्रारंभ हो गई हैं तो इस स्थिति में सिंचाई न करें, चने की फसल में दूसरी सिंचाई 50% फली बनने की अवस्था में करें। चने की फसल में फली आना प्रारंभ हो गए हैं, फली बनने के समय फली छेदक कीट के आक्रमण की ज्यादा संभावना होती है अतः रोकथाम हेतु इन्डोक्साकार्ब 14.5% 58 @ 12-15ml/ पंप की दर से स्प्रे करें। चने की फसल में प्रारम्भिक कीट नियंत्रण हेतु एकीकृत कीट प्रबंधन का प्रयोग जैसे फेरोमोन प्रपंच, प्रकाश प्रपंच या खेतों में पक्षियों के बैठने हेतु खूटी लगाना लाभकारी होता है।

सरसों : पिछले कुछ दिनों से बादल रहने के कारण सरसों की फसल में चूर्णिल आसिता वीमारी के प्रकोप की संभावना बन रही है अतः फसल की सतत निगरानी करते रहें तथा अधिक प्रकोप होने पर 20 कि.ग्रा. गंधक चूर्ण का भुरकाव करें या 750 मि.ली. डाइनोकेप (केराथेन 30 एल.सी.) को पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें। अल्टरनेरिया ब्लाइट, डाउनी मिल्ड्यू और लीफ स्पॉट के लिए लगातार निगरानी रखें, यदि कोई बीमारी दिखे तो मैनकोजेब 75% WP 2-5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। रस चूसने वाले कीटों के लिए लगातार निगरानी रखें, यदि संक्रमण दिखे तो थायोमेथोक्सम 5.0-7.5 ग्राम/पंप 0.35-0.5 ग्राम/लीटर का स्प्रे करें।

आलू : आलू फसल में कंद बन चुका है यह सिंचाई की क्रांतिक अवस्था है। अतः आवश्यकतानुसार सिंचाई करने की सलाह दी जाती है। आलू में रसचूसक कीटों का प्रकोप देखा जा रहा हैं अतः सलाह है कि नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड 0.5 मिली/लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें।

आम : आम के बाग में सिंचाई करना बंद करें। आम में मिलिबग को नियंत्रित करने के लिए तने में ग्रीस स्ट्रिप्स का उपयोग करें और फॉलिडॉल 250 ग्राम/पौधा की दर से मिट्टी में उपयोग करें। बेर के पौधों में फलों की अच्छी वृद्धि के लिए नाइट्रोजन धारी उर्वरक के रूप में यूरिया का छिड़काव करें।

पशुपालन : दलहनी चारा फसल जैसे बरसीम, लूसर्न आदि को सूखे चारे के साथ मिलाकर कुट्टी काटकर खिलायें। पशुओं को पौष्टिक हरा चारा खिलाने के लिए उसे फूल आने के पहले ही कटाई करें। पशुओं को ठंड से बचाने हेतु पक्के फर्श को धान की पुआल या कूड़े से आच्छादित करें जो थर्मल मल्व प्रदान करता है। सभी दुग्ध जानवरों को रात के दौरान विशेष रूप से संरक्षित और सुरक्षित मवेशी शेड में रखें। पशुशाला में पशुओं को मच्छरों एवं अन्य कीटों से बचाव हेतु गीला कूड़ा-कचरा जलाकर धुआँ करें।

ऑनलाईन सदस्यता के लिए लॉग इन करें
www.krishakjagat.org

स्वास्थ्य

दाल-चावल : प्रोटीन और ऊर्जायुक्त भोजन

क्यों हमारा रोज़मर्रा का आरामदायक भोजन आज की प्रोटीन-दीवानगी से अधिक स्वास्थ्यवर्धक और समझदारी भरा हो सकता है

● डॉ. राघवेन्द्र साहू ● डॉ. चन्द्रहास साहू
दुग्ध विज्ञान एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, रायपुर
ercsahu2003@yahoo.com

आज के समय में प्रोटीन सबसे अधिक चर्चा में रहने वाला पोषक तत्व बन गया है। जिम की बातचीत से लेकर सुपरमार्केट की शेल्फ़ तक, यह सुर्खियां, पैकेजिंग और सोशल मीडिया क्षेत्र पर छाया हुआ है। प्रोटीन पाउडर, बार, फ़ोर्टिफ़ाइड स्नैक्स, प्लांट-बेस्ड मीट और लैब-निर्मित विकल्प सब ताक़त, फिटनेस और दीर्घायु का वादा करते हैं, वह भी अक्सर ऊँची कीमत पर। लेकिन इसी शोर-शराबे के बीच, भारत के करोड़ों घर आज भी चुपचाप और निरंतर अपनी प्रोटीन ज़रूरतें एक ऐसे भोजन से पूरी कर रहे हैं, जो शायद ही कभी सुर्खियों में आता है- दाल और चावल। सरल, सस्ता और अत्यंत परिचित यह संयोजन पीढ़ियों से विभिन्न क्षेत्रों, ऋतुओं और सामाजिक-आर्थिक वर्गों को पोषण देता आ रहा है।

आधुनिक पोषण विज्ञान अब जिस तथ्य की पुष्टि कर रहा है, वह बेहद सरल है-दाल और चावल मिलकर एक उच्च गुणवत्ता वाला, पोषण की दृष्टि से पूर्ण पौध-आधारित प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन ट्रेंड्स के अस्तित्व में आने से बहुत पहले, भारतीय रसोई ने पोषण संतुलन की इस समस्या का समाधान खोज लिया था।

दाल और चावल साथ में बेहतर क्यों

चावल, जो कई पारंपरिक आहारों का मुख्य अनाज है, ऊर्जा का उत्कृष्ट स्रोत है, लेकिन इसकी अमीनो अम्ल संरचना असंतुलित होती है। इसके प्रोटीन में ग्लूटामिन, प्रोलिन, ल्यूसीन और एलैनिन की मात्रा अधिक होती है, जबकि लाइसिन, ट्रिप्टोफ़ैन, मेथियोनीन और हिस्टिडिन जैसे पोषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण अमीनो अम्ल सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। यद्यपि चावल में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल मौजूद होते हैं- विशेष रूप से अंकुर (जर्म) में- फिर भी कम लाइसिन के कारण इसकी प्रोटीन गुणवत्ता सीमित रह जाती है।

इसके बावजूद, चावल से प्राप्त प्रोटीन आइसोलेट्स को अत्यंत पौष्टिक माना जाता है और उनकी गुणवत्ता केसिन तथा सोया प्रोटीन के समकक्ष पाई गई है। उच्च पाचन-क्षमता और कम एलर्जेनिक गुणों के कारण चावल प्रोटीन शिशुओं और वृद्धों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है और इसे पशु-आधारित प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण विकल्प माना जाता है। फिर भी, अकेला चावल आवश्यक अमीनो अम्लों की पूर्ति आदर्श रूप से नहीं कर पाता।

यहीं दालें इस पोषणीय कमी को प्रभावी ढंग से पूरा करती हैं। दालों में अनाजों की तुलना में लगभग दोगुनी मात्रा में प्रोटीन (लगभग 21-25 प्रतिशत) पाया जाता है और ये लाइसिन, फोलेट, आयरन, मैग्नीशियम, पोटैशियम और जिंक से भरपूर होती हैं। यद्यपि दालों में मेथियोनीन और सिस्टीन जैसे सल्फ़र-युक्त अमीनो अम्ल सीमित होते हैं, फिर भी इनके प्रोटीन अंश-मुख्यतः ग्लोब्युलिन और एल्ब्यूमिन-लाइसिन, आर्जिनिन और एस्पार्टिक अम्ल से समृद्ध होते हैं। एल्ब्यूमिन, यद्यपि कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इसकी घुलनशीलता बेहतर होती है, जिससे पकाने और पाचन के दौरान यह स्टार्च और जल के साथ बेहतर अंतःक्रिया कर पाता है।

यद्यपि दाल प्रोटीन की पाचन-क्षमता संरचनात्मक कठोरता और कुछ प्रतिपोषक तत्वों के कारण अपेक्षाकृत कम होती है, लेकिन जब इन्हें अनाज के साथ मिलाया जाता है तो कुल प्रोटीन उपयोगिता में सुधार होता है। चावल दालों में कमी वाले सल्फ़र-युक्त अमीनो अम्ल प्रदान करता है, जबकि दालें चावल की लाइसिन की कमी को पूरा करती हैं। इस प्रकार दोनों मिलकर एक संतुलित और पूर्ण अमीनो अम्ल प्रोफ़ाइल बनाते हैं, जो उच्च गुणवत्ता वाले पशु प्रोटीन के समकक्ष होती है।

पोषण विज्ञान में इस सिद्धांत को प्रोटीन पूरकता (Protein Complementation) कहा जाता है। भारतीय आहार में यह अवधारणा सदियों से सहज रूप से अपनाई जाती रही है। इसलिए दाल-चावल का यह स्थायी संयोजन संयोग नहीं, बल्कि अनुभव, संस्कृति और जैविक अनुकूलता से विकसित पोषणीय बुद्धिमत्ता का परिणाम है जो इसे विश्व के सबसे टिकाऊ और पोषण-कुशल पौध-आधारित भोजनों में से एक बनाता है। **(क्रमशः)**

केसर : महकती औषधि

यूं तो केसर का उत्पत्ति स्थान दक्षिणी यूरोप का स्पेन देश है, जहां से केसर मुम्बई आई है और मुम्बई से पूरे भारत के बाजारों में पहुंचती है, लेकिन स्पेन के अलावा केसर की पैदावार ईरान, फ्रांस, इटली, ग्रीस, तुर्की, फारस और चीन में भी की जाती है। भारत में, कश्मीर के पम्पूर नामक स्थान पर और जम्मू के किश्तवाड़ नामक स्थान पर केसर की खेती की जाती है।

केसर का उपयोग : आयुर्वेदिक नुस्खों में, खाद्य व्यंजनों में और देव पूजा आदि में तो इसका उपयोग होता ही था पर अब पान

मसालों और गुटकों में भी इसका उपयोग होने लगा है। केसर बहुत ही उपयोगी गुणों से युक्त होती है। यह उत्तेजक, वाजीकारक, यौनशक्ति बनाए रखने वाली होती है। कामोत्तेजक, त्रिदोष नाशक, रुचिकर, मासिक धर्म साफ लाने वाली, गर्भाशय व योनि संकोचन जैसे रोगों को भी दूर करती है। त्वचा का रंग उज्ज्वल करने वाली, रक्तशोधक, धातु पौष्टिक, प्रदर और निम्न रक्तचाप को ठीक करने वाली, कफ नाशक, मन को प्रसन्न करने वाली, स्तन (दूध) वर्द्धक, मस्तिष्क को बल देने वाली, हृदय और रक्त के लिए हितकारी, तथा खाद्य पदार्थ और पेय (जैसे दूध) को रंगीन और सुगन्धित करने वाली होती है।

स्वास्थ्यवर्धक है श्रीफल

नारियल एवं इसका पानी दोनों ही काफी गुणकारी हैं तथा औषधि के रूप में घरेलू उपयोग में लाए जाते हैं। नारियल का पानी दूध की तरह ही एक पूर्ण आहार है। विटामिन के रूप में इसमें 'ए, बी, सी' विटामिन साथ में प्रोटीन, कैल्शियम एवं लौह तत्व पाए जाते हैं। ये सभी तत्व शरीर के विकास हेतु अत्यंत लाभदायक माने जाते हैं। यदि नारियल का और इसके पानी का उचित समय पर सही उपयोग किया जाए तो घरेलू प्रकार की कई छोटी-छोटी तकलीफों पर काबू किया जा सकता है।

● **हिचकी** –कच्चे नारियल का पानी पीने से हिचकी खत्म होती है। साथ ही उल्टी, पेट की गैस, पेटदर्द में भी लाभ होता है।

● **दमा** – नारियल की जटा को जलाकर और पावडर (राख) को शहद में मिलाकर दिन में तीन-चार बार चाटने से अच्छा फायदा होता है।

● **याददाश्त** – नारियल की गिरी में बादाम, अखरोट एवं मिश्री मिलाकर सेवन करने से स्मृति शक्ति में वृद्धि होती है।

● **नकसीर** – नाक से खून निकलने पर कच्चे नारियल का पानी नियमित रूप से पीना चाहिए। साथ ही खाली पेट नारियल के सेवन से भी रक्त का बहाव रुक जाता है।

● **मुहाँसे** – नारियल के पानी में खीरे का रस मिलाकर सुबह-शाम नियमित रूप से लगाने से चेहरे के दाग मिटते हैं। चेहरा सुंदर एवं चमकदार हो जाता है। नारियल के तेल में नींबू का रस अथवा ग्लिसरीन मिलाकर चेहरे पर लेप करने से भी मुहाँसे मिटते हैं।

● **अनिद्रा** – रात के भोजन पश्चात नियमित रूप से आधा गिलास नारियल पानी पीना चाहिए। इससे नींद अच्छी आती है।

● **सिरदर्द** – नारियल तेल में बादाम को मिलाकर तथा बारीक पीसकर सिर पर लेप लगाना चाहिए। इससे सिरदर्द में शीघ्र लाभ होता है।

● **रूसी** – नारियल के तेल में नींबू का रस मिलाकर बालों में लगाने से रूसी एवं खुश्की से छुटकारा मिलता है।

● **गर्भावस्था में** – सुबह नियमित रूप से 50 ग्राम नारियल की गिरी को चबाने से गर्भवती महिला को स्वास्थ्य में तो लाभ होता ही है। साथ ही गर्भस्थ बालक भी गौरवर्ण का एवं हृष्ट-पुष्ट होता है।

● **पेट के कीड़े** – पेट में कीड़े होने पर सुबह नाश्ते के समय एक चम्मच पिसा हुआ नारियल का सेवन करने से पेट के कृमि शीघ्र ही मर जाते है।

पाक्षिक पंचांग

2 से 15 मार्च 2026 तक
विक्रम संवत् 2082
फाल्गुन शुक्ल 14 से चैत्र कृष्ण 11 तक

दि.	माह	वार		तिथि	त्यौहार
02	मार्च	सोम	फाल्गुन शुक्ल	14	होलिका दहन
03	मार्च	मंगल	----------	15	होली उत्सव, चंद्रग्रहण
04	मार्च	बुध	चैत्र कृष्ण	1	बसंतोत्सव
05	मार्च	गुरु	----------	2	भाई दोज
06	मार्च	शुक्र	----------	3	गणेश चतुर्थी व्रत
07	मार्च	शनि	----------	4	
08	मार्च	रवि	----------	5	रंग पंचमी
09	मार्च	सोम	----------	6	एकनाथ छठ
10	मार्च	मंगल	----------	7	भानु सप्तमी
11	मार्च	बुध	----------	8	शीतलाष्टमी
12	मार्च	गुरु	----------	9	
13	मार्च	शुक्र	----------	10	
14	मार्च	शनि	----------	11	खरमास प्रारंभ
15	मार्च	रवि	----------	11	पापमोचनी एकादशी

फॉलोअप

नमूना परीक्षण रिपोर्ट नहीं मिलने से मामला अटका

शिवपुरी जिले में फफूंदनाशक से चना और मसूर फसल हुई थी खराब

इंदौर (कृषक जगत)। गत दिनों शिवपुरी जिले के खतौरा में फफूंदनाशक के छिड़काव से 10 गांवों के किसानों की चना और मसूर की फसल ख़राब होने का मामला सामने आया था। इस बहुचर्चित मामले में किसानों की शिकायत के बाद कृषि विभाग ने जांच दल गठित किया था। कृषि विभाग द्वारा संबंधित दुकान से एकत्रित सैंपलों को जांच के लिए भेजकर दुकान को बंद कर दिया गया था। जांच प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित विक्रेता अग्रवाल कृषि सेवा केंद्र, खतौरा, कम्पनी श्रीकर बायोटेक प्रा. लि. के जोनल मैनेजर एवं शिवपुरी प्रभारी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज़ की गई थी। घटना के करीब एक माह बाद भी एकत्रित नमूनों की परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने से मामला अटक गया है।

उल्लेखनीय है कि शिवपुरी जिले के खतौरा, एडवारा, विजरौनी आदि 10 गांवों के किसानों ने अग्रवाल कृषि सेवा केंद्र, खतौरा से श्रीकर बायोटेक प्रा. लि. कम्पनी का फफूंदनाशक उत्पाद कलिंगा खरीदा था, जिसका किसानों ने जब चना और मसूर फसल पर छिड़काव किया तो पट्टियां जल गई और पत्ते सूख गए थे। इससे क्षेत्र की बड़े रकबे की फसल प्रभावित हुई थी। किसानों की शिकायत के बाद इस मामले में श्री पानसिंह करोरिया ,उप संचालक कृषि, शिवपुरी ने जांच दल गठित किया था। जांच दल द्वारा फसलों का निरीक्षण किया गया, जिसमें किसानों की शिकायत को सही पाया गया। जांच दल के प्रतिवेदन के आधार पर श्री के कोली,वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, बदरवास द्वारा अग्रवाल कृषि सेवा केंद्र, खटावरा के संचालक मनोज जैन,श्रीकर बायोटेक प्रा. लि. के जोनल मैनेजर रामवीरसिंह यादव और शिवपुरी प्रभारी मनोज जैन के खिलाफ संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज़ कराई गई थी।

उक्त मामले में श्री के. कोली,वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, बदरवास ने कृषक जगत को बताया कि दुबारा फसल का निरीक्षण किया गया था, जिसमें फसल खड़ी हो गई थी, लेकिन चना फसल में फूल कम पाए गए थे। गर्मी के कारण फूल से फल में बदलने की संभावना कम दिखाई दी। मसूर फसल में उकठा रोग था। उसमें दवाई नहीं डाली गई थी। संबंधित दुकान से एकत्रित किए गए नमूनों की परीक्षण रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। जहां तक किसानों को मुआवजा देने का प्रश्न है, तो इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अब यह मामला न्यायालय के अधीन है।

राजगढ़ और धार के कृषि मेले में

कोरोमंडल इंटरनेशनल को मिला प्रथम पुरस्कार

राजगढ़/धार (कृषक जगत)। हाल ही में राजगढ़ और धार जिले में आयोजित कृषि मेले, देश की प्रसिद्ध कम्पनी कोरोमंडल इंटरनेशनल लि. की टीम ने सक्रिय भागीदारी करते हुए

किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों एवं पोषक तत्व प्रबंधन की विस्तृत जानकारी प्रदान की। राजगढ़ मेले में सांसद श्री रोडमल नागर , जिला कलेक्टर श्री गिरीश कुमार मिश्रा तथा पूर्व विधायक एवं मंत्री श्री रघुनंदन शर्मा ने कोरोमंडल कम्पनी के स्टॉल का अवलोकन किया और उत्पादों के बारे में जानकारी प्राप्त की।

मेले के दूसरे दिन कृषि विभाग, राजगढ़ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में एग्रोनॉमिस्ट श्री भास्कर तिवारी को एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन विषय पर व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की विस्तृत जानकारी दी तथा ग्रोमोर के प्रमुख उत्पाद ग्रोप्लस, ग्रोमोर nDAP एवं ग्रोअल्फा के बारे में विस्तार से बताया। अंत में किसानों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर भी दिए गए।

मेले के तीसरे दिन बड़ी संख्या में किसानों ने स्टॉल पर पहुंचकर उत्पादों की जानकारी प्राप्त की। टीम द्वारा ग्रोमोर nDAP, ग्रोप्लस, ग्रोअल्फा तथा GNC ऐप के बारे में किसानों को मार्गदर्शन दिया गया। इस दौरान किसानों ने ग्रोमोर nDAP की खरीदारी भी की। किसानों के प्रति समर्पण को देखते हुए मेला प्रबंधन समिति द्वारा ग्रोमोर टीम को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर श्री भास्कर तिवारी (एग्रोनॉमिस्ट, राजगढ़) के साथ श्री इकरार खान (MDT), श्री विशाल परमार (MDT) एवं श्री अभिजीत शर्मा (MDT) की सक्रिय सहभागिता रही।

इसी तरह धार जिले में कृषि विभाग द्वारा आयोजित तीन दिवसीय कृषि मेले का समापन हुआ। किसान इस मेले में आधुनिक खेती और उन्नत तकनीकों के प्रदर्शन हेतु विभिन्न संस्थाओं ने सहभागिता की। तीन दिनों तक चले इस आयोजन

में कोरोमंडल इंटरनेशनल द्वारा किसानों के लिए विशेष गतिविधियों का संचालन किया गया, जिसमें लकी ड्रा स्कीम और नवाचारी खेल शामिल हैं। मेले के दौरान प्रदर्शित उत्कृष्ट प्रदर्शनी और किसान जुड़ाव गतिविधियों के आधार पर कोरोमंडल इंटरनेशनल को विभाग द्वारा प्रथम स्थान दिया गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथियों द्वारा संस्था को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए शील्ड और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

डॉ. दीक्षित को लाइफटाइम एकेडमिक लीडरशिप अवॉर्ड

चंडीगढ़ (कृषक जगत)। डॉ. अनिल दीक्षित, संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान को गत दिनों आयोजित AGRIMMET 2026 के समापन समारोह में 'लाइफटाइम एकेडमिक लीडरशिप अवार्ड' से सम्मानित किया गया। सम्मेलन का आयोजन एग्री मीट फाउंडेशन भारत द्वारा किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि डॉ. धीर सिंह, निदेशक-सह-कुलपति, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल रहे। इस अवसर पर पंजाब क्षेत्र के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, वरिष्ठ वैज्ञानिक तथा लगभग 400 प्रतिभागी उपस्थित रहे।

इंदौर जिले में 16 मार्च तक होगा चना पंजीयन, 61 केन्द्र बनाए

इंदौर (कृषक जगत)। रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए इंदौर जिले में चना उपार्जन के लिये किसान अपनी फसल का पंजीयन आगामी 16 मार्च तक करा सकते हैं। चना उपार्जन के लिए पंजीयन विगत 20 फरवरी से प्रारंभ हो गए हैं। जिले में चना पंजीयन के लिए पर्यवेक्षण एवं मॉनिटरिंग एवं नियंत्रण के लिए जिला स्तरीय उपार्जन प्रशासकीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति में अध्यक्ष सहित कुल 11 सदस्यों को शामिल किया गया है। समिति के अध्यक्ष कलेक्टर श्री शिवम वर्मा है। अपर कलेक्टर श्री रोशन राय ने बताया कि जिले में किसानों की सुविधा के लिए पंजीयन की व्यवस्था को सहज और सुगम बनाई गई है। जिले की देपालपुर तहसील में सर्वाधिक 26 पंजीयन केन्द्र बनाये गए हैं।

78 वर्ष
कृषक जगत
राष्ट्रीय कृषि अखबार
भोपाल-जयपुर-रायपुर

वर्ष में कई आकर्षक एवं संग्रहणीय विशेषांक
- खरीफ विशेषांक
- पौध संरक्षण विशेषांक
- रबी विशेषांक
- बीज विशेषांक
- बागवानी विशेषांक

25 लाख पाठक

कृषक जगत की सदस्यता राशि
➪ वार्षिक रु. 600/-
➪ दो वर्ष रु. 1000/-
➪ तीन वर्ष रु. 1500/-

डाक से नियमित रूप से 'कृषक जगत' – प्रति सप्ताह ☐ भोपाल ☐ जयपुर ☐ रायपुर संस्करण निम्न पते पर एक वर्ष/दो वर्ष / तीन वर्ष भेजें. (अपनी आवश्यकता के अनुरूप निशान लगायें).

नाम .....
.....
ग्राम .....पो. .....
डाक वितरण हेतु अपने क्षेत्रीय पोस्टमैन का मो. नं. अवश्य दें : .....
वि.ख. ..... तह. .....
जिला ..... पिन ☐☐☐☐☐☐ राज्य .....
शिक्षा ..... भूमि ..... उम्र .....
ट्रैक्टर/मॉडल ..... फोन/मो. .....
ई-मेल .....
मेरा सदस्यता शुल्क रुपये ..... नगद/डिमांड ड्राफ्ट/UPI/Bank/
मनीऑर्डर/क्र. ..... 'कृषक जगत' भोपाल के नाम संलग्न है।

कृषक जगत में सदस्यता लेने के माध्यम
कृषक जगत ऑनलाइन पेमेंट लिंक
http://www.krishakjagat.org/krishak-jagat-subscription/index.php
Online Payment- SBI-A/C No. 53007193070, IFSC : SBIN 0005793,
Google Pay/Phone Pe/PAYTM/UPI : Mobile 9826255861
कृषक जगत हेल्पलाइन नम्बर 6262166222

पेमेंट के बाद : 1. पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजें इस फोन नम्बर पर 9826255861
2. पूरा नाम, पता पिन कोड के साथ भेजें।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें
प्रसार प्रबंधक कृषक जगत

भोपाल : 14, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल-462011 फोन: 0755-4248100, मो. : 9926653355, 9826255861, E-mail-info@krishakjagat.org
जयपुर : एच-64, मीरा मार्ग, बनी पार्क, जयपुर (राज.), मो. : 9829254092, 7387422952
रायपुर : एलआईजी-5, सेक्टर-2, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.),मो.: 9826255862
इंदौर : 331-332, आर्बिट माल, ए.बी. रोड, विजय नगर चौराहे के पास इंदौर, मो. : 9826021837, 9826024864
नई दिल्ली : 403,आईएनएस बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली, मो. : 7387422952

सदस्यता शुल्क भुगतान के लिए QR कोड स्कैन करें

ऑनलाईन सदस्यता के लिए लॉग इन करें
www.krishakjagat.org

छिंदवाड़ा में भव्य कृषि मेला एवं मिलेट फूड फेस्टिवल

छिंदवाड़ा (कृषक जगत)। छिंदवाड़ा जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग द्वारा आयोजित तीन दिवसीय जिला स्तरीय कृषि मेला एवं मिलेट फूड फेस्टिवल सह रोड शो 2026 का गत दिनों पोला ग्राउंड (दशहरा मैदान) में शुभारम्भ हुआ। मेले

की औपचारिक शुरूआत कलेक्टर श्री हरेंद्र नारायन, पुलिस अधीक्षक श्री अजय पाण्डेय, नगर निगम महापौर श्री विक्रम अहके, श्री शेषराव यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री संजय पुन्हार और मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड भोपाल श्रीमती सी.सरस्वती द्वारा किया गया। इस अवसर पर सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने मेला स्थल में लगे जिले के एफपीओ, स्व सहायता समूहों, कृषकों एवं पड़ोसी जिले नरसिंहपुर, डिंडौरी, मंडला के किसानों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया और विभिन्न उत्पादों के संबंध में जानकारी भी प्राप्त की। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों द्वारा मिलेट्स जागरूकता रोड शो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अन्य जनप्रतिनिधिगण, उप संचालक कृषि श्री जितेन्द्र कुमार सिंह सहित कृषि एवं सह सम्बंध विभागों के सभी अधिकारी, कृषि वैज्ञानिक, कृषक भाई एवं बहनें, गणमान्य नागरिक और पत्रकार उपस्थित थे।

छिन्दवाड़ा कृषि मेले में मंच पर मौजूद नाबार्ड मुख्य महाप्रबंधक श्रीमती सी. सरस्वती, कलेक्टर श्री हरेन्द्रनारायण, एसपी श्री पांडे, भाजपा जिलाध्यक्ष एवं महापौर छिन्दवाड़ा सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी कृषक जगत का अवलोकन करते हुए।

कृभको: व्यापार बैठक में उपलब्धियों पर मंथन

भोपाल (कृषक जगत)। कृषक भारती को-ऑपरेटिव लि. (कृभको) ने वित्त वर्ष 2026-27 हेतु व्यापार योजना बैठक का आयोजन किया। कार्यक्रम में कृभको के विपणन निदेशक श्री मनीष कुमार, संयुक्त महाप्रबंधक- विप. एवं जोनल हेड डॉ. प्रदीप कुमार, संयुक्त महाप्रबंधक- विप. श्री तेजिंदर सिंह, उप महाप्रबंधक- विप. डॉ. राजीव कुमार, उप महाप्रबंधक- विप. श्री अजय सिंह, वरि. प्रबंधक लेखा श्री जतिन बजाज, सहायक प्रबंधक श्री मोहित, क्षेत्रीय प्रबंधक इंदौर श्री राज बाबू कुमार, वरि. अधिकारी लेखा श्री लोकेश साहनी एवं प्रदेश में कार्यरत समस्त अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

2025-26 में किये गए कार्यों एवं बिक्री लक्ष्यों की समीक्षा, वर्ष 2026-27 के लिए आवंटित लक्ष्यों पर चर्चा एवं संशोधन, विपणन एवं बिक्री रणनीति निर्धारण, वर्तमान बाजार की स्थिति एवं प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण, लक्षित ग्राहकों की पहचान, डिजिटल मार्केटिंग एवं सोशल मीडिया प्रचार की योजना, संभावित जोखिम (बाजार प्रतिस्पर्धा, लागत वृद्धि) एवं उनके समाधान, शासन द्वारा समय समय पर लागू की जाने वाली योजनाओं एवं कृषि नियमों के अनुपालन तथा कृभको द्वारा कृषकों के लिए आयोजित होने वाले प्रोन्नत कार्यक्रम, योजनाओं एवं उत्पादों को कृषि क्षेत्र से जुड़े अंतिम उपभोक्ता तक सही समय एवं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने जैसे विषयों पर चर्चा की गई।

एनएफएल ने विक्रेताओं को बताए विपणन के तरीके

शिवपुरी (कृषक जगत)। नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. (एनएफएल) के क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर द्वारा शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, श्योपुर जिले के थोक उर्वरक विक्रेताओं का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। कार्यक्रम में एनएफएल के आंचलिक प्रबंधक श्री जीआर शर्मा, राज्य प्रबंधक मप्र श्री एमएल चौधरी, कृषि विज्ञान केंद्र के श्री एमके भार्गव, श्री विजय प्रताप सिंह, सीए श्री आशीष गोयल मौजूद थे। क्षेत्रीय अधिकारी श्री केएम पाठक ने एनएफएल की प्रगति, विपणन पर विक्रेताओं के निरंतर सहयोग की सराहना की। कार्यक्रम का संचालन जिला प्रभारी गुना श्री अम्बालाल गहलोत ने किया। कार्यक्रम का समापन जिला प्रभारी शिवपुरी श्री मनीष मीणा, जिला प्रभारी ग्वालियर श्री मनोज कुमार (लेखा पर्यवेक्षक) द्वारा संयुक्त रूप से धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

इंदौर में सेमिनार एवं पुष्प प्रदर्शनी

इंदौर (कृषक जगत)। कृषि वर्ष के उपलक्ष्य में गत दिनों ग्रामीण हाट बाजार ढक्कन वाला कुआं, इंदौर में एकीकृत बागवानी विकास मिशन एवं प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना अंतर्गत जिला स्तरीय दो दिवसीय सेमिनार एवं पुष्प प्रदर्शनी कार्यक्रम आयोजित की गयी। इस मौके पर उप संचालक उद्यान श्री टी.सी. वास्कले ने विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। मार्केटिंग विशेषज्ञ श्री राकेश अग्रवाल ने उद्यानिकी फसलों की मार्केटिंग एवं निर्यात संभावनाओं पर प्रकाश डाला। वरिष्ठ वैज्ञानिक श्री पी.जी. नाडकर्णी ने उन्नत फूल खेती की आधुनिक तकनीकों से अवगत कराया। डॉ. पूजा पाण्डे ने मशरूम उत्पादन को अतिरिक्त आय के प्रभावी माध्यम के बारे में बताया। परियोजना संचालक आत्मा श्रीमती शरली थॉमस ने प्राकृतिक खेती के महत्व पर जानकारी दी।

पटवारी एग्रो एजेन्सी

:: वितरक ::

◆ कलश सीड्स लि. ◆ बायोस्टेट इंडिया लि. ◆ बॉयर कॉप साइंस ◆ धानुका एग्रीटेक लि.
◆ एफ.एम.सी. इंडिया प्रा.लि. ◆ घरड़ा केमिकल्स लि. ◆ अतुल एग्रीटेक लि.
◆ रामा फॉस्फेट्स लि. ◆ जी.एन.एफ.सी. ◆ इंसेक्टीसाइड्स इंडिया लि. ◆ बीएएसएफ
◆ डयूपॉन्ट इंडिया लि. ◆ क्रिस्टल क्राप साइंस ◆ डाउएग्रो साइंसेस ◆ एग्री सर्च इंडिया
◆ मंशा इंडिया लि. ◆ स्वाल कार्पोरेशन लि. ◆ मेघमनी आर्गेनिक्स ◆ अदामा इंडिया लि.

17, विशाल टॉवर, इंदिरा काम्पलेक्स, नवलखा चौराहा, इन्दौर (म.प्र.)
फोन : 2403694, 2400412, मो. : 9425077083

भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नर्सरी
ISO 9001 : 2015 सर्टिफाईड
किसान हाईटेक ग्रीनहाऊस नर्सरी
द्वारा पपीता, मिर्च, टमाटर, बैंगन, तरबूज, करेला, पत्तागोभी, फूलगोभी आदि सब्जी के पौधे टेबल स्टेण्ड के ऊपर रखकर तैयार किए जाते हैं
सम्पर्क : 9407361901, 9407361902, 9407361903
सहयोगी प्रतिष्ठान : बागवानी बाजार नर्सरी जहां पर फलदार, सजावटी व फारेस्टी पौधों की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है। **संपर्क : मो.** : 9407853117, 9407853118, 9407853119, **नर्सरी स्थल : ग्राम-सिरलाय, तह.- बड़वाह 451115, जिला-खरगोन (म.प्र.)**
मार्च 26

TerraGlebe Farmers Producer Company Limited
NIMADFRESH
यूरोप में मिर्च निर्यात (एक्सपोर्ट) करने वाला मध्यप्रदेश का पहला किसान उत्पादक संगठन बना 'टेरागलेब'
अब उसी की तर्ज पर नाबार्ड से गठित FPO निमाड़फ्रेश FPO रसायन मुक्त मसाले का बना मैन्युफैक्चर ODOP - मिर्च-खरगोन
जुलाई 26

निमाड़फ्रेश FPO (JV)	टेरागलेब FPO
हरिओम भुरे	बालकृष्ण पाटीदार
8964087240	9575524408

छोटा विज्ञापन बड़ा लाभ

व्यक्तिगत क्लासीफाइड

विज्ञापन के लिए निर्धारित कैटेगरीज-
- बेचना/खरीदना- ट्रैक्टर, ट्राली, थ्रेशर, खेत, मकान, मोटरसाइकल, पशु, मोटर, जनरेटर आदि ▪ बीज ▪ औषधीय फसल

विज्ञापन दर - मात्र रु. 600/- प्रति संस्करण लगातार 4 सप्ताह तक ▪ अधिकतम 25 शब्द
- अतिरिक्त शब्द- 2 रु. प्रति शब्द, अधिकतम 40 शब्दों तक

डिस्प्ले क्लासीफाइड

विज्ञापन दर : रु. 800/- प्रति अंक, प्रति संस्करण जीएसटी 5% अतिरिक्त
साइज : फिक्स साइज- 8 × 5 = 40 वर्ग से.मी.

कैटेगरीज- बीज, कीटनाशक, जैविक खाद, ट्रेक्टर्स, तीर्थ यात्राएं, आवश्यकता, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, कृषि सेवा केन्द्र, शिक्षण संस्थाएं, प्रशिक्षण, बारदाने, कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, होस्टल, वित्तीय संस्थाएं, चिकित्सक, एग्री क्लीनिक आदि।

कृषक जगत
की सदस्यता एवं विज्ञापन के लिए हेल्पलाइन नं.
62 62 166 222
www.krishakjagat.org @krishakjagatindia
@krishakjagat @krishak_jagat

एरीज ग्रुप की कंपनी

अमारक केमिकल्स ने दुबई में सल्फर प्लांट शुरू किया

नई दिल्ली (कृषक जगत)। एरीज ग्रुप की सहयोगी कंपनी अमारक केमिकल्स ने दुबई के जेबेल अली में अपने पूर्णत: आटोमेटिक सल्फर प्लांट का संचालन प्रारम्भ कर दिया है। नए संयंत्र की वार्षिक स्थापित क्षमता 60,000 मीट्रिक टन है, जिसमें सल्फर बेंटोनाइट तथा अन्य वैल्यू एडेड सल्फर-आधारित कृषि इनपुट्स का निर्माण किया जाएगा। यह इकाई अंतरराष्ट्रीय बाजारों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्थापित की गई है, विशेषकर उन क्षेत्रों के लिए जहां मिट्टी में सल्फर की कमी पाई जाती है।

कारखाने का उद्घाटन भारत के महावाणिज्य दूतावास, दुबई के कौंसुल श्री बी. जी. कृष्णन द्वारा किया गया। इस अवसर पर जाफ़ज़ा के सेल्स निदेशक सऊद अलअवाधी तथा एरीज ग्रुप के निदेशक मंडल के सदस्य उपस्थित रहे।

अमारक वर्तमान में दक्षिण अमेरिका और एशिया-प्रशांत क्षेत्र सहित 13 देशों में निर्यात करता है, जिनमें ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड शामिल हैं। एरीज ग्रुप के अध्यक्ष डॉ. राहुल मीरचंदानी ने कहा कि जाफ़ज़ा में यह निवेश कृषि इनपुट्स के क्षेत्र में विश्वस्तरीय विनिर्माण क्षमता विकसित करने की समूह की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है। उद्घाटन समारोह में सात देशों से आए ग्राहकों ने संयंत्र का दौरा किया और इसकी ऑटोमेशन प्रणालियों का अवलोकन किया।

जेके टायर ने 'श्रेष्ठ प्लस' ट्रैक्टर टायर लॉन्च किया

हिसार (कृषक जगत)। जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लि. ने आधुनिक कृषि की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपना नया प्रीमियम ट्रैक्टर टायर 'श्रेष्ठ प्लस' लॉन्च किया है। कंपनी का कहना है कि यह टायर बढ़ती कृषि यंत्रीकरण, अधिक हॉर्सपावर वाले ट्रैक्टरों के उपयोग और विभिन्न प्रकार की मिट्टी में लंबे समय तक काम करने की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है।

कंपनी के अनुसार, 'श्रेष्ठ प्लस' को बेहतर ट्रैक्शन, स्थिरता और लंबी उम्र देने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है, ताकि किसान और कृषि कार्य से जुड़े ऑपरेटर खेत और सड़क—दोनों परिस्थितियों में बेहतर कार्यक्षमता प्राप्त कर सकें।

जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लि. के डायरेक्टर (सेल्स एंड मार्केटिंग) श्री श्रीनिवासु अल्लाफन ने कहा कि भारतीय कृषि तेजी से यंत्रीकरण की ओर बढ़ रही है और किसान अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर अपना रहे हैं। ऐसे में कंपनी का ध्यान उच्च प्रदर्शन

वाले समाधान उपलब्ध कराने पर है। जेके टायर का कहना है कि उसका कृषि टायर पोर्टफोलियो विभिन्न प्रकार की मिट्टी, ट्रैक्टर श्रेणियों और कृषि कार्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, और 'श्रेष्ठ प्लस' इसी श्रृंखला को और मजबूत करता है।

आईपीएल को कांडला बंदरगाह पर सम्मान

नई दिल्ली (कृषक जगत)। उर्वरक क्षेत्र की प्रमुख कंपनी इंडियन पोटाश लि. (आईपीएल) को अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2026 के अवसर पर कांडला बंदरगाह और विशाखापत्तनम बंदरगाह पर उत्कृष्ट आयात प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। आईपीएल को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए गुजरात के कांडला बंदरगाह पर 'टॉप इम्पोर्टर' का पुरस्कार दिया गया।

'टॉप इम्पोर्टर' पुरस्कार गांधीधाम स्थित इफको ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में दिया गया। यह पुरस्कार कांडला के सीमा शुल्क आयुक्त श्री नितिन सैनी ने मुख्य अतिथि पद्मश्री सम्मानित श्री नारायण जोशी (कच्छ) की उपस्थिति में प्रदान किया। आईपीएल की ओर से गुजरात (कच्छ) के सेल्स ऑफिसर श्री जतिन शाह ने यह पुरस्कार प्राप्त किया।

आईपीएल के प्रबंध निदेशक डॉ. पी.एस. गहलौत ने कहा 'ये सम्मान हमारे आयात कार्यों में उत्कृष्टता, नियमों के पालन और विश्वसनीयता पर हमारे मजबूत फोकस को दर्शाते हैं। यह देशभर के बंदरगाहों और लॉजिस्टिक्स केंद्रों पर काम कर रही हमारी टीम की मेहनत का परिणाम है।'

पारादीप फॉस्फेट्स को S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी ईयरबुक 2026 में स्थान

बेंगलुरु (कृषक जगत)। पारादीप फॉस्फेट्स लि. (पीपीएल) को S&P Global की S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी ईयरबुक 2026 में सस्टेनेबिलिटी ईयरबुक सदस्य के रूप में चुना गया है। साथ ही, वर्ष 2026 में ईयरबुक में स्थान पाने वाली यह भारत की एकमात्र उर्वरक कंपनी बनी है।

श्री एन. सुरेश कृष्णन

श्री राजीव नांबियार

S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी ईयरबुक 2026 उन कंपनियों को मान्यता देती है, जो अपने-अपने उद्योगों में पर्यावरण, सामाजिक और सुशासन (ESG) मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करती हैं। इस वर्ष 2025 के कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट (CSA) के तहत 9,200 से अधिक कंपनियों का मूल्यांकन किया गया, जिनमें से 59 उद्योगों की केवल 848 कंपनियां 2026 संस्करण में स्थान बना सकीं।

पीपीएल के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ श्री एन. सुरेश कृष्णन ने कहा, 'यह सम्मान एक जिम्मेदार और भविष्य के लिए तैयार उद्यम के निर्माण की हमारी दीर्घकालिक दृष्टि को दर्शाता है। फॉस्फेटिक उर्वरक उद्योग में अग्रणी कंपनी के रूप में हम सस्टेनेबिलिटी को भारत की कृषि प्रगति और राष्ट्रीय विकास का अभिन्न हिस्सा मानते हैं।'

कंपनी के अध्यक्ष एवं मुख्य परिचालन अधिकारी श्री राजीव नांबियार ने कहा, 'पीपीएल में सस्टेनेबिलिटी हमारी पूरी वैल्यू चेन में समाहित है-चाहे वह सुशासन ढांचे को मजबूत करना हो, परिचालन दक्षता बढ़ाना हो या जिम्मेदार सोर्सिंग और विनिर्माण उत्कृष्टता को आगे बढ़ाना हो।'

आईटीसी कृषि को एआई के जरिए दे रही नया रूप

नई दिल्ली (कृषक जगत)। उन्नत डिजिटल तकनीकों के माध्यम से छोटे और सीमांत किसानों को हाइपर-पर्सनलाइज्ड समाधान उपलब्ध कराने के बाद, आईटीसी अब अपने एआई नवाचारों का विस्तार एफपीओ, जैविक खेती किसानों और ग्रामीण समुदायों तक करने जा रही है। नई जेनरेटिव एआई एप्लीकेशन और एजेंटिक एआई क्षमताओं के माध्यम से कंपनी अपने ITCMAARS 'फिजिटल' इकोसिस्टम को एक सशक्त, कनेक्टेड और इंटेलिजेंस-ड्रिवन एग्री-स्टैक में परिवर्तित कर रही है। यह पहल आईटीसी के चेयरमैन श्री संजीव पूरी की 'नेक्स्ट जेन एग्रीकल्चर' रणनीति का अहम हिस्सा है। आईटीसी का लक्ष्य ITCMAARS प्लेटफॉर्म के माध्यम से 1 करोड़ किसानों तक पहुंच बनाना है, जिससे ग्रामीण विकास को गति मिले।

एफपीओ और जैविक खेती के लिए एआई समाधान- ITCMAARS एक सुपरएप के रूप में डिजिटल तकनीक और जमीनी मानव संपर्क का संयोजन है, जिसमें एफपीओ को एंकर की भूमिका दी गई है। एफपीओ के लिए अलग कस्टमाइज्ड ऐप भी उपलब्ध है। अब कंपनी एफपीओ संचालन की दक्षता बढ़ाने और उन्हें स्केल-अप करने के लिए एआई आधारित समाधान जोड़ने जा रही है।

आईटीसी एग्री बिजनेस के डिविजनल चीफ एग्जीक्यूटिव श्री एस. गणेश कुमार ने कहा कि कंपनी का उद्देश्य नवीनतम तकनीकों तक छोटे किसानों की पहुंच को लोकतांत्रिक बनाना है, ताकि वे जलवायु परिवर्तन, फसल प्रबंधन और बाजार पहुंच जैसी चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपट सकें।

एआई इम्पैक्ट समिट में प्रमुख उदाहरण- नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान ITCMAARS को जमीनी स्तर पर एआई के प्रभावी उपयोग के उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। यह पहल 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' की भारतीय एआई सोच के अनुरूप है।

22 लाख किसान जुड़े, आय में 25% तक वृद्धि- 2022 में शुरू हुआ ITCMAARS अब फुल-स्टैक 'फार्मिंग ऐज़ अ सर्विस' समाधान बन चुका है। 11 राज्यों में 22 लाख से अधिक किसान और 2100 से ज्यादा एफपीओ इससे जुड़े हैं। पायलट आकलनों के अनुसार- उर्वरक उपयोग में 10-15% कमी, फसल उत्पादकता में 15-20% वृद्धि, किसानों की आय में लगभग 25% इजाफा।

'कृषि मित्र' बना किसानों का एआई सहायक- इस इकोसिस्टम का मुख्य आधार 'कृषि मित्र' है, जो माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से विकसित एआई आधारित एग्री-को-पायलट है। 8 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध।

'क्रॉप कैलेंडर' और 'क्रॉप डॉक्टर' से सटीक सलाह- ITCMAARS पर उपलब्ध 'क्रॉप कैलेंडर' 53 फसलों के लिए वैज्ञानिक फसल योजना बनाने में मदद करता है। वहीं 'क्रॉप डॉक्टर' एआई आधारित इमेज एनालिटिक्स टूल है, जो 70 फसलों में रोग पहचान कर त्वरित उपचार सलाह देता है। इस फीचर का 3 लाख से अधिक बार उपयोग किया जा चुका है।

- **आईटीसी एफपीओ, जैविक किसानों और ग्रामीण समुदायों तक एआई समाधान का विस्तार करेगी**
- **ITCMAARS अब उन्नत एआई तकनीकों से लैस फुल-स्टैक 'फार्मिंग ऐज़ अ सर्विस' (FaaS) प्लेटफॉर्म बना**
- **11 राज्यों में 22 लाख से अधिक किसान और 2100 से ज्यादा एफपीओ लाभान्वित**
- **उर्वरक उपयोग में 10-15 प्रतिशत कमी, पैदावार में 15-20 प्रतिशत वृद्धि, किसानों की आय में लगभग 25 प्रतिशत इजाफा**

तिवड़ा वापस आ रहा है !

● शशिकांत त्रिवेदी,
वरिष्ठ पत्रकार
मो.: 9893355391

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के वैज्ञानिक तिवड़ा वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे आमतौर पर खेसरी और घास मटर के नाम से जाना जाता है। किसानों की एक सभा को संबोधित करते हुए हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जल्द ही बाज़ार में एक नई कम नुकसानदायक किस्म आएगी। तिवड़ा का भारत में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता था लेकिन बाद में इस पर रोक लगा दी गई क्योंकि यह इंसानों में लेथिरिज्म बीमारी पैदा करती थी। कृषि मंत्री श्री चौहान ने कहा, 'हम अलग-अलग किस्मों से दाल का प्रोटीन निकालने के लिए प्रयोग कर रहे हैं ताकि किसानों को ज़्यादा फ़ायदा हो सके।

भंडारण पर रोक लगी

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के वैज्ञानिक तिवड़ा की उन किस्मों को तैयार कर रहे हैं जिनमे न्यूरोटॉक्सिन का स्तर काफ़ी कम हो और ये सुरक्षित किस्में हों। तिवड़ा इंसानों में न्यूरोलैथिरिज्म नाम की एक बीमारी पैदा करता है जिससे लंबे समय तक इस्तेमाल करने से पैरों में खराबी आ जाती है। इस टॉक्सिन को पहले न्यूरोलैथायरिज्म से जोड़ा गया है, जो एक पैरालिटिक डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से 1961 से भारत में खेसरी/तिवड़ा की बिक्री और भंडारण पर रोक लगी है। कोशिशें इस तरह की जा रही हैं कि इस विषैले तत्व को कम करके इंसानों के इस्तेमाल के बजाय सुरक्षित किस्म विकसित करने पर ज़ोर दिया जा रहा है।

अन्य तकनीकों का इस्तेमाल

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् राज्य की एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर जारी की गई खास वैरायटी में रतन और प्रतीक शामिल हैं। इनमें इस विषैले तत्व का प्रतिशत 0.07 से 0.1 प्रतिशत तक होता है, जो रिस्की माने जाने वाले लेवल से काफी नीचे है, और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार और ओडिशा जैसे सही इलाकों में 1.5 से 1.6 टन प्रति हेक्टेयर तक पैदावार देता है। शोधकर्ताओं ने पूसा-24 वैरिएंट से रतन जैसी लाइनें बनाने के लिए कन्वेंशनल हाइब्रिडाइजेशन, टिशू कल्चर और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल किया।

गरीब आदमी की दाल

अभी चल रहे काम में आनुवंशिक संशोधन की गुंजाईश भी है, विषैले तत्व को पूरी तरह खत्म किया जा सके। अभी शोध इस बात पर है कि सूखे की स्थिति में तिवड़ा में पाया जाने वाले विषैले तत्व का स्तर बढ़ सकता है। सन् 2023 से 2025 तक की हालिया शोध में पूर्वी भारत, खासकर बिहार में खेसरी को उगाकर देखा गया है, ताकि चावल की कटाई के बाद कम इस्तेमाल होने वाली ज़मीनों में दालों का उत्पादन बढ़ाया जा सके। तिवड़ा या खेसरी को 'गरीब आदमी की दाल' का नाम इसलिए मिला है क्योंकि यह बहुत ज़्यादा सूखे, पानी भरने और बंजर मिट्टी में भी उगती है, जहाँ दूसरी फसलें नष्ट हो जाती हैं। इसमें ज़्यादा प्रोटीन होता है, यह लगभग 125 दिनों में जल्दी पक जाती है, और खाने और चारे के तौर पर दोनों तरह से इस्तेमाल की जा सकती है। रतन और प्रतीक जैसी कम विषैले तत्व वाली किस्मों को खेती के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन कमर्शियल बिक्री के लिए बड़े पैमाने पर मंजूरी अभी भी फ़ूड सेफ़्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया और इंडियन काउंसिल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च के अधीन है।

'स्मार्ट दाल'

कुछ राज्यों ने पाबंदियां हटाने की तैयारी कर ली हैं, और कुछ संस्थानों के अध्ययन के मुताबिक, नई किस्मों का कम इस्तेमाल दिल की बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। यह शोध बदलते पर्यावरण के हालात के बीच पौष्टिक भोजन की सुरक्षा और छोटे किसानों के लिए एक 'स्मार्ट दाल' के तौर पर दिलचस्पी पैदा करती है।